नई दिल्ली ■ गुरुवार 11 दिसंबर 2025 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 253 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 विकसित भारत का मूल मंत्र बनेगा 'वंदे मातरम्' | 07 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में शुभमन गिल पर रहेगी नजर | 'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' रिलीज 08

दीपावली उत्सव यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल

नयी दिल्ली। भारत के प्रमुख उत्सव दीपावली को बुधवार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। दिल्ली में लाल किले पर आयोजित यूनेस्को की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया।

यह पहली बार है कि भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के संरक्षण के लिए अंतरसरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस समिति का 20वां सत्र लाल किले में आठ से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा दीपावली उत्सव को प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' के नारे हवा में गूंज उठे। विभिन्न पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने मुख्य मंच के सामने प्रस्तुति दी और एक बड़ी स्क्रीन पर दीपावली उत्सव के चित्र प्रदर्शित किए गए।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की ओर से एक बयान दिया। यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 16वीं सांस्कृतिक परंपरा है। भारत की 15 सांस्कृतिक परंपराएं वर्तमान में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हैं, जिनमें कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला - महाकाव्य 'रामायण' का पारंपरिक प्रदर्शन शामिल हैं। शेखावत और भारतीय दल के अन्य सदस्यों ने इस अवसर पर पारंपरिक पगड़ी पहनी। प्रकाश का उत्सव दीपावली भारत के उन चिरस्थायी त्योहारों में से एक है जो अब दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को पारंपरिक दीयों से सजाते हैं और इमारतों को रोशन किया जाता है, जिससे रात में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है। भारत ने 2024-25 के लिए 2023 में यूनेस्को को दीपावली नामांकन का दस्तावेज भेजा था।

शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि हर भारतीय के लिए दीपावली बेहद भावनात्मक त्योहार है; इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है, इसे महसूस किया जाता है और आत्मसात किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दीपावली को इस सूची में शामिल करके 'यूनेस्को ने नवीकरण, शांति और अच्छाई की जीत के लिए शाश्वत मानवीय अभिलाषा का सम्मान किया है। शेखावत ने कहा कि कुम्हारों से लेकर कारीगरों तक लाखों हाथ इस विरासत को जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूनेस्को का यह 'टैग' भी एक जिम्मेदारी है और 'हमें सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली हमेशा एक विरासत बनी रहे।' उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि दीपावली राम राज्य यानी सुशासन का त्योहार है। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली पर लोगों को 'एक अतिरिक्त दीपक जलाना चाहिए, कृतज्ञता का दीपक, शांति का दीपक, मानवता की साझेदारी का दीपक और सुशासन का दीपक।

यूनेस्को का दर्जा मिलने से दीपावली की वैश्विक लोकप्रियता में वृद्धि होगी: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और वृद्धि होगी। मोदी ने यूनेस्को द्वारा दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किये जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता का सार है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी अधिक वृद्धि होगी। मोदी ने कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श हमारा शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें। प्रकाश के त्योहार दीपावली को बुधवार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दिल्ली के लाल किले में हुई यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

इंडिगो संकट पर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से किया सवाल

'ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई'

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से बुधवार को सवाल किया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जिसके कारण इंडिगो की कई उड़ान रद्द करनी पड़ीं। अदालत ने इन हालात को 'संकट' करार दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को हुई परेशानी और उत्पीड़न के अलावा, यह अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का भी सवाल है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह सवाल भी किया कि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में दूसरी विमानन कंपनियां हालात का फायदा उठाकर यात्रियों से टिकटों के लिए भारी कीमत कैसे वसूल सकती हैं। अदालत ने सवाल किया कि जो टिकट 5,000 रुपये में मिल रहा था, उसका मूल्य 30,000 से 35,000 रुपये तक कैसे पहुंच गया? यदि यह संकट की स्थिति थी तो दूसरी विमानन कंपनियों को इसका लाभ कैसे उठाने दिया गया? किराया 35,000 और 39,000 रुपये तक कैसे पहुंच गया? अन्य विमानन कंपनियों ने शुल्क लेना कैसे शुरू कर दिया? पीठ ने इस मामले पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की। पीठ ने कहा कि यदि समिति द्वारा शुरू की गई जांच पूरी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट अगली तारीख 22 जनवरी को अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए। अदालत ने कहा कि हम नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन हमें यह चिंता है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होने दी गई, जिसके कारण पूरे देश के हवाई अड्डों पर लाखों यात्री फंसे रहे।

पीठ ने कहा कि यह न सिर्फ यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, क्योंकि मौजूदा समय में यात्रियों का तेज आवागमन अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि कानूनी प्रावधान पूरी तरह लागू हैं और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसने काफी क्षमायाचना की है। सरकार के वकील ने यह भी कहा कि यह संकट कई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण पैदा हुआ, जिनमें चालक दल के सदस्यों के उड़ान की ड्यूटी के घंटों से संबंधित नियम भी शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि किराए में जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई थी, उसे अब नियंत्रित और सीमित कर दिया गया है, जो पहले किया जाना चाहिए था। अदालत इंडिगो द्वारा सैकड़ों उड़ान रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को सहायता और भुगतान की गई राशि वापस दिलाने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि याचिका बिना सोच-विचार और दस्तावेजों के दाखिल कर दी गई। इंडिगो की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यह संकट कई कारणों और कुछ अप्रत्याशित समस्याओं के कारण उत्पन्न हुआ।

डीजीसीए का इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन, गुरुवार दोपहर 3 बजे किया तलब

मुंबई। विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय में उपस्थित होने और हालिया परिचालन व्यवधानों से संबंधित व्यापक एवं अद्यतन जानकारी से लैस एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। एल्बर्स को बृहस्पतिवार को दोपहर तीन बजे डीजीसीए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि सीईओ को सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

इंडिगो संकट पर नजर रखेगा डीजीसीए, आठ सदस्यीय निगरानी दल गठित

मुंबई। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के हालिया संकट के बीच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन इंडिगो पर निगरानी कड़ी कर दी है। डीजीसीए ने बुधवार को आठ सदस्यों वाली निगरानी टीम गठित की है, जिसमें दो सदस्यों को इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में तैनात किया जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जारी आदेश में कहा कि राहुल भाटिया के नियंत्रण वाली एयरलाइन कंपनी इंडिगो में चालक दल की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद 8 सदस्यीय निगरानी दल गठित किया गया है। इस निगरानी दल में एक उपमुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक और दो अन्य उड़ान संचालन निरीक्षक शामिल होंगे। इनमें से दो सदस्य रोजाना इंडिगो के मुख्य कार्यालय में तैनात रहेंगे। उन्हें एयरलाइन के पूरे बेड़े, औसत उड़ान दूरी, कुल पायलटों की संख्या, नेटवर्क विवरण, चालक दल के सेवा के घंटे, प्रशिक्षण में लगे चालक दल और अन्य संबंधित मामलों की निगरानी करनी होगी।

श्रद्धालुओं की बस राजस्थान में ट्रक से टकराई

4 की मौत, 28 लोग घायल

अहमदाबाद। गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सीकर जिले के फतेहपुर के पास मंगलवार देर रात खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रही वलसाड (गुजरात) की स्लीपर बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस भीषण हादसे में बस यात्री मयंक पटेल निवासी वलसाड और बस ड्राइवर कमलेश चौधरी निवासी डूंगरी महुआ, सूरत की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य यात्री की मृतक की पहचान अमित के रूप में हुई है जो बागड़ झुँझुनू का बताया जा रहा है। वहीं, बस कंडक्टर मितेश को गंभीर हालत में सीकर के एसके हॉस्पिटल से जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन बुधवार सुबह इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। कुल 28 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 7 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुजरात के तीर्थयात्री वैष्णोदेवी से लौट रहे थे हादसे के शिकार अधिकतर यात्री गुजरात के रहने वाले थे। सभी जम्मू स्थित वैष्णोदेवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे और रास्ते में खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन की योजना थी। रात को खाटू में रुकने का उनका प्लान था, लेकिन इससे पहले ही फतेहपुर में यह भीषण दुर्घटना हो गई।

घायलों को सीकर और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीमें इलाज में लगातार जुटी हैं। पुलिस घायल और मृत यात्रियों के परिवारों को सूचना भेज रही है।

बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टक्कर के बाद कार में लगी आग, पांच की मौत व छह झुलसे

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दो कारों की आमने-सामने की टक्कर के बाद आग लग गई। जिससे महिलाओं और बच्चियों सहित पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना के पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

संक्षिप्त खबरें

मप्र : हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान हादसे का शिकार, पायलट घायल

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ढाना हवाई पट्टी पर एक इंजन का छोटा ट्रेनी विमान उस हादसे का शिकार हो गया, जब वह रनवे पर उतर रहा था। लैंडिंग के दौरात अनियंत्रित होने के बाद विमान (एयरक्राफ्ट) की नोज जमीन से आ टकराई। हवाई पट्टी पर मौजूद कर्मचारी तुरंत दौड़े और पायलट को बाहर निकाला। विमान में दो पालट सवार थे, जिन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल रूम में भेजा गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। हादसा बुधवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ। चाइम्स एविएशन एकेडमी के इस एयरक्राफ्ट को ट्रेनी पायलट उड़ा रहे थे। चाइम्स एविएशन एकेडमी के कर्मचारियों के मुताबिक लैंडिंग के वक्त पायलट का एयरक्राफ्ट से नियंत्रण छूट गया। वह एक तरफ झुककर रनवे से नीचे आकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त ढाना हवाई पट्टी से सड़क दुर्घटना में घायल एक जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा था।

महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में 82 लाख के 11 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

मुंबई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को 11 नक्सलियों पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें डिवीजनल कमेटी के सदस्य, प्लाटून कमेटी के सदस्य, एरिया कमेटी के सदस्य जैसे उच्च पदस्थ नक्सली शामिल थे और इन सभी पर 82 लाख रुपये का इनाम था। इनमें से चार माओवादी हथियारों के साथ और पूरी वर्दी में मौजूद थे। कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा रखी गई थी। इससे पहले 15 अक्टूबर को माओवादी आंदोलन के सबसे सीनियर नेताओं में से एक भूपति उर्फ सोनू मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने सीएम फडणवीस की मौजूदगी में 61 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था।

नाइटक्लब आग मामला: साझेदार अजय गुप्ता पुलिस हिरासत में

फरार मालिकों को अदालत से कोई राहत नहीं

पणजी/नई दिल्ली। गोवा पुलिस ने बुधवार को 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के साझेदार अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया और दिल्ली की एक अदालत ने उसकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की याचिका को भी स्वीकार कर ली। पिछले सप्ताहांत नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गयी थी। उत्तरी गोवा स्थित इस क्लब में निवेशक और साझेदार होने का दावा करने वाले गुप्ता को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गोवा पुलिस के अनुरोध पर हिरासत में लिया।

गुप्ता को बाद में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए गोवा पुलिस को उनकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड सौंप दी। गुप्ता को दिल्ली में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने के बाद हिरासत में लिया गया था। न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रीढ़ की हड्डी में चोट से पीड़ित गुप्ता को गोवा ले जाते समय उचित चिकित्सा देखभाल और समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए। इस बीच, आग लगने के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड भागे नाइटक्लब के फरार मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दिल्ली की अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे। लूथरा बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने गोवा अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस अब भी सक्रिय है। आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय कर दी।

दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी आग की घटना के सिलसिले में गोवा पुलिस ने पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले एक व्यापक सुरक्षा अभियान की घोषणा की।

भारत-ब्राजील नौसेनाओं के बीच क्षमता निर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई सहमति

नौसेना प्रमुख ने ब्राजीलियन नेवी के कमांडर से वार्ता में कई अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया

नई दिल्ली। ब्राजील के चार दिवसीय दौरे पर गए नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बुधवार को ब्राजीलियन नेवी के कमांडर एडमिरल मार्कोस सैम्पाइओ ओल्सन से मुलाकात की। भारत-ब्राजील के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के मकसद से बातचीत हुई, जिसमें ऑपरेशनल जुड़ाव, ट्रेनिंग का आदान-प्रदान, हाइड्रोग्राफिक सहयोग, जानकारी शेयर करने और समुद्री डोमेन के बारे में जागरुकता बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नौसेना के मुताबिक रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और दोनों नौसेनाओं के बीच क्षमता निर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। भारत और ब्राजील के बीच समुद्री साझेदारी मजबूत होने से ग्लोबल मैरीटाइम कॉमन्स ग्लोबल साउथ में स्थिरता लाने में मिलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना और ब्राजील की नौसेना के बीच मजबूत और बढ़ती समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ करना है। यह भारत-ब्राजील व्यापक सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 12 दिसंबर तक ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो, ब्राजील सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ प्रमुख एडमिरल रेनाटो रोड्रिग्स डी अगुइर फ्रेयर के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय समुद्री सहयोग की समीक्षा करने, परिचालन-स्तरीय संबंधों को बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका प्रदान करेगी। इस यात्रा में परिचालन कमांडों के साथ बैठकें, नौसैनिक अड्डों और ब्राजील की नौसेना के शिपयार्डों का दौरा भी होगा। बातचीत के दौरान साझा समुद्री प्राथमिकताओं, नौसैनिक अंतर-संचालन, क्षमता निर्माण और व्यापक दक्षिण-दक्षिण सहयोग सहित बहुपक्षीय ढांचे के भीतर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नौसेना प्रमुख की यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, व्यावसायिक आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में ब्राजील की नौसेना के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इससे वैश्विक समुद्री क्षेत्र में स्थिरता लाने में योगदान मिलेगा।

यमुना विकास प्राधिकरण ने दनकौर में 500 करोड़ की सरकारी भूमि मुक्त कराई

ग्रेटर नोएडा। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने बुधवार को दनकौर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। टीम ने सरकारी और प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर बने टिनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, स्थायी और अस्थायी निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर करीब 500 करोड़ की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक दनकौर में कॉलोनाइजर और माफिया ने करीब 4.6 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। वे अवैध निर्माण कर प्लॉटिंग कर रहे थे। प्राधिकरण को इसके बारे में शिकायत मिली थी। इस पर प्राधिकरण की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खसरा नंबर 211 पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर करीब 500 करोड़ की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया। बताया गया कि यह भूमि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बनने वाले इंटरचेंज से प्रभावित किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड देने के लिए है। इसके साथ ही, अन्य भूमि पर कई विशेष परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इस कार्रवाई से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे औद्यो गिक और शहरी विकास के लिए आरक्षित भूमि पूर्ण रूप से मुक्त हो गई। ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी से लागत वसूलने के साथ उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। दोपहर से शाम तक कार्रवाई चली: यमुना विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दोपहर करीब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, जोकि शाम पांच बजे तक चली। इस दौरान छह से अधिक बुलडोजर ने अवैध रूप से खड़ी की गई टिनशेड, पक्की-कच्ची दीवारें, झोपड़ियां तथा अन्य स्थायी-अस्थायी निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं, टीम की कार्रवाई देख आसपास मौजूद कॉलोनाइजर भाग खड़े हुए। कई अवैध कॉलोनी आकार ले चुकी: यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और हाथरस तक है। ऐसे में अतिक्रमण रोकना चुनौती पूर्ण कार्य है। कॉलोनाइजर नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक के निकट होने का दावा कर लोगों को भूखंड बेच रहे हैं। इनमें भूखंडों का क्षेत्रफल 50 से 200 गज तक है। यहां आवास के लिए रिहायशी जमीन 16000-18000 प्रति वर्गमीटर और व्यावसायिक जमीन 18,000 से 20,000 रुपये प्रति गज के रेट पर बेची जा रही है। यही कारण है कि नोएडा एयरपोर्ट के पास कई अवैध कॉलोनी आकार ले चुकी हैं। कॉलोनाइजर्स ने यहां फर्जी टाउनशिप दिखाकर ब्रॉशर छपा रखे हैं। इतना ही नहीं कॉलोनाइजर्स ने पक्की सड़क तक बना ली है। कॉलोनाइजर नोएडा एयरपोर्ट के पास 15 हजार रुपये गज के रेट पर लोगों को भूखंड का फर्जी बैनामा थमाकर उनसे लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं।

जेवर टोल के बाद से शुरू हो जाती हैं फर्जी टाउनशिप यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर टोल प्लाजा पार करते ही फर्जी टाउनशिप का खेल शुरू हो जाता है। सिमरौती गांव में एक प्रोजेक्ट श्रीतुलसी वाटिका के नाम से दर्शाया गया है। यह 200 बीघा जमीन पर दिखाया गया है। इसका बाकायदा ब्रॉशर तक जारी हो चुका है। इसके अलावा अपना घर प्रोजेक्ट, श्री हरि वाटिका, गंगा सिटी प्रोजेक्ट हैं। इनमें भूखंड बेचे जा रहे हैं। वीकेंड पर फर्जी टाउनशिप में भूखंड बेचने के लिए लोगों को गाड़ियां से ले जाया जाता है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीम गठित है। साथ ही, आम लोगों से भी कॉलोनाइजरों के बहकावे में न आने की अपील की जा रही है।

एनपीसीएल की टीम पर हमले के मामले में मुकदमा दर्ज

ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र के चिरसी गांव में मंगलवार को बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची एनपीसीएल की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो ग्रामीणों को नामजद किया है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कासना कोतवाली पुलिस के मुताबिक एनपीसीएल की टीम मंगलवार को चिरसी गांव में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची थी। टीम की जांच में पाया गया कि ग्रामीण सोनू बिना मीटर के सर्विस केबल को सीधे लाइन से जोड़कर बिजली चोरी कर रहा है। एक कर्मचारी ने पोल से केबल काटने की कोशिश की तो सोनू और उसके साथी संजीव शर्मा ने विरोध किया। कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद टीम को वहां से भगा दिया। इस मामले में एनपीसीएल के सहायक प्रबंधक अवधेश फुलजडे ने कासना कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपी सोनू और संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच कर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक सिग्नल पर दो कार टकराईं, चालक घायल

नोएडा। सेक्टर-70 की ट्रैफिक सिग्नल पर बुधवार दोपहर दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में दोनों कारों के चालक घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई है। फेज-3 थाना पुलिस ने बताया कि सेक्टर-70 स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में कार चालक मोनू यादव निवासी इटावा और अमरेश पाल निवासी एटा घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को कार से बाहर निकाला और स्ट्रैचर की मदद से एंबुलेंस तक पहुंचाया। वहां से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि ट्रैफिक लाइट होने के बाद भी कार चालकों ने तेजी से गाड़ी चलाई, जिससे हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर भरी भीड़ जमा हो गई। साथ ही, जाम की स्थिति बन गई। क्षतिग्रस्त कारों को क्रेन की मदद से हटाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हुआ।

संक्षिप्त खबरें

नोएडा डिपो ने चालकों की भर्ती के लिए मांगे आवेदन

नोएडा। मोरना स्थित नोएडा डिपो ने संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। लोग कार्यदिवस में नोएडा डिपो में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। नोएडा डिपो में 800 से अधिक चालक और परिचालक हैं। इनमें संविदाकर्मियों की संख्या अधिक है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में कुल मिलाकर 305 बसें हैं। इसमें नोएडा डिपो में बसों की संख्या 188 है। सभी साधारण और सीएनजी से चलने वाली बसें हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। लंबाई कम से कम 5.3 फीट, योग्यता कम से कम आठवीं पास और भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। दस्तावेजों की जांच के बाद चालक का बस चलाने का परीक्षण किया जाएगा। यदि इसमें भी वह सफल होता है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा चालकों के अलावा महिला परिचालकों की भर्ती पर भी कार्य चल रहा है। चयनित महिला परिचालकों की सोमवार तक सूची डिपो में चस्पा कर दी जाएगी।

मिडडे मील में बच्चों को बाजरे का लड्डू और गजक मिलेगी

नोएडा। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पोषक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत हर गुरुवार छात्रों को गुड़-तिल-मूंगफली की गजक, चौलाई या बाजरे का लड्डू अथवा भुना चना दिया जाएगा। मार्च के आखिरी सप्ताह तक यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मिडडे मील योजना के तहत मिलने वाले नियमित भोजन के अलावा यह अतिरिक्त आहार फ्लैक्सी फंड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मिडडे मील प्राधिकरण के निदेशक की ओर से बीएसए को सर्कुलर भेजा गया है। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना में निर्धारित बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल बजट के छह प्रतिशत हिस्से का उपयोग फ्लैक्सी फंड के रूप में किया जाएगा। इसी मद से परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री दी जाएगी।

खाली भूखंड में खड़े दो ई-रिक्शा की बैटरी चोरी

दादरी। घोड़ी बछेड़ा गांव में खाली भूखंड में खड़े दो ई-रिक्शा की आठ बैटरी चोरी कर ली गईं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घोड़ी बछेड़ा गांव में राहुल परिवार के साथ रहता है। राहुल ने पुलिस को बताया कि वह और उसके साथी सत्येंद्र ग्रेटर नोएडा में ई-रिक्शा चलाते हैं। उन दोनों ने मंगलवार की रात अपने दोनों ई-रिक्शा खाली भूखंड में खड़े किए थे। बुधवार की सुबह उन्हें पता चला कि दोनों ई-रिक्शा से आठ बैटरी चोरी हो गई हैं। पीड़ित राहुल ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी जा रही है। चोरों का पता लगा कर चोरी की गई बैटरी बरामद की जाएंगी।

सोसाइटी में बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज-तीन सोसाइटी में बुधवार को करीब चार घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ। सोसाइटी में रहने वाले मृत्युंजय ने बताया कि परिसर में करीब 1500 परिवार रहते हैं, लेकिन लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। सोसाइटी में सुबह 11 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो दोपहर दो बजे केवल आधे घंटे के लिए बिजली आई, जिसके बाद वह फिर से चली गई। शाम चार बजे आपूर्ति शुरू हुई, लेकिन ट्रिपिंग की समस्या बनी रही। सोसाइटी में रहने वाले अंकित ने बताया कि कई बार ट्रिपिंग की वजह से लोगों के फ्रिज और अन्य उपकरण खराब हो चुके हैं। आरोप है कि लाइट जाने पर डीजी चलाने पर 27 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से शुल्क लिया जाता है, जो अधिक है।

जेवर विधायक ने 12 करोड़ की सड़क परियोजना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया

नोएडा। जेवर विधानसभा के लिए धर्मार्थ योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर लगभग 8 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। यह मार्ग 5.50 मीटर चौड़ाई का बनेगा, जो तहसील जेवर से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के सामने से होते हुए ग्राम साहब नगर, ग्राम सिरसा माचीपुर व ग्राम जेवर खादर मढ़ैया को जोड़ते हुए बांध एवं ग्राम रामपुर बांगर तक पहुंचेगा। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, आवागमन सुगम होगा तथा दर्जनों ग्रामों को सीधा लाभ मिलेगा।

विधायक धीरेंद्र सिंह ने क्षेत्र के लोगों के साथ उपरोक्त संपर्क मार्ग का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जेवर क्षेत्र में निरंतर किए जा रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से सशक्त बनाना है, और यह संपर्क मार्ग उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर विधानसभा के विकास के लिए जो सतत सहयोग और संवेदनशीलता दिखाई है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

12 करोड़ की लागत से स्वीकृत यह 8 किलोमीटर लंबाई का मार्ग, जो तहसील जेवर से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के सामने से होकर ग्राम साहब नगर, सिरसा माचीपुर, जेवर खादर मढ़ैया होते हुए बांध और रामपुर बांगर तक जाएगी, जो दर्जनों ग्रामों के लिए विकास की नई धुरी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि यह मार्ग न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीणों की कृषि और रोजमर्रा की सुविधाओं तक पहुंच को भी सुगम बनाएगा।

बिल्डर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज

ग्रेटर नोएडा। हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति ने बिल्डर और उसके कर्मचारियों पर रुपये लेकर फ्लैट पर कब्जा नहीं देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बिल्डर समेत निदेशक और मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले तरुण कुमार कौशिक ने न्यायालय को बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने ग्रेनो वेस्ट में एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बिल्डर प्रबंधन को करीब साढ़े छह लाख रुपये देकर फ्लैट की बुकिंग करवाई। इसके बाद बिल्डर की तरफ से पीड़ित को एक बैंक से करीब 40 लाख रुपये का लोन दिलवाया गया। पीड़ित के रुपये और बैंक से मिले लोन की रकम बिल्डर ने अपने खाते में जमा कर ली। इसके बाद पीड़ित को फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। पीड़ति ने फ्लैट का कब्जा देने की बात की तो इधर-उधर की बात की जाने लगी। पीड़ति के दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी दे गई। पीड़ित का आरोप है कि उसके करीब 46.39 लाख रुपये हड़प लिए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिसरख कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

उप्र में हो रहे हर गैर कानूनी काम में भाजपा के लोगों का हाथ: अखिलेश

नोएडा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उन सबमें भाजपा के लोगों का हाथ है। सपा अध्यक्ष बुधवार को एक कार्यक्रम के सिलसिले में गौतमबुद्ध नगर पहुंचे जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला और कहा कि विपक्ष की सक्रियता से भाजपा की नींद हराम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जब से कफ सिरप वाला मामला आया है, बुलडोजर का चालक चाबी लेकर और बुलडोजर छोड़कर भाग गया है। अब मुख्यमंत्री के पास ना चालक है ना चाबी है।" यादव ने पूछा कि पहले तो बुलडोजर से न्याय मिलता था लेकिन अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है।

उन्होंने कहा, "बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कफ सिरप के मामले में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के सजातीय लोग शामिल हैं, जिससे जांच कराई जा रही है वह भी उनके सजातीय हैं। एसटीएफ के लोग भी कफ सिरप मामले में शामिल थे। इसलिए जब से भाजपा वालों के नाम आए हैं तब से बुलडोजर का चालक चाबी लेकर भाग गया है।" घुसपैठ और बांग्लादेशियों को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि कोई भी घुसपैठिया नहीं है। अगर भाजपा सरकार के 11 साल के बाद भी घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा प्रमुख ने एसआईआर की भी आलोचना की। पार्टी ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, "यह एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं, अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हम पीडीए वालों को निकालेंगे।" फिल्म सिटी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म सिटी की क्या जरूरत है क्योंकि भाजपा सरकार में पहले से ही कई 'कलाकार' मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र विवाद पार्टी है। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम्, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा देकर भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सहित देश के बड़े-बड़े क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि इनको लेकर भाजपा हर जगह विवाद ढूंढती है। यह राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्र विवाद पार्टी है।" उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेटर नोएडा की गंदगी नदियों के माध्यम से कन्नौज और फिर गंगा में मिलती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री गंगा नदी को साफ करना चाहते थे लेकिन गंगा तो अब तक साफ नहीं हुई, पर उत्तर प्रदेश का बजट जरूर 'साफ' हो गया है।

सदरपुर कॉलोनी से किशोर लापता

नोएडा। सदरपुर कॉलोनी में रहने वाला 15 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सदरपुर कॉलोनी निवासी संजीव मिश्रा ने बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा पांच दिसंबर से गायब है। अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। उन्होंने बेटे के साथ अनहोनी होने की आशंका जाहिर की है। किशोर की सकुशल बरामदगी के लिए थाना स्तर पर एक टीम गठित कर दी गई है।

शिवम मावी और हर्ष त्यागी पर IPL में बोली लगेगी

नोएडा। शहर के शिवम मावी और हर्ष त्यागी पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट में बोली लगेगी। ऑक्शन में शामिल क्रिकेटरों की सूची मंगलवार को जारी की गई। 16 दिसंबर को फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी टीम में खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए अबुधाबी में बोली लगाएंगी। शिवम कई बार आईपीएल में अलग-अलग टीमों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हर्ष त्यागी अभी किसी टीम से नहीं खेल पाए हैं।

शिवम मावी का बेस प्राइस 75 लाख रुपये है। वहीं, हर्ष त्यागी का बेस प्राइस 30 लाख रुपये निर्धारित है। शिवम मावी पहले 32 आईपीएल मुकाबले खेल चुके हैं। वहीं हर्ष त्यागी के हिस्से अब तक एक भी मैच नहीं है। शिवम ने भारतीय टीम की ओर से छह अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबले भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने सात विकेट अपने नाम किए हैं। बता दें कि शिवम का आईपीएल में 32 मुकाबलों में 30 विकेट झटके हैं। 2018 से वह आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। पिछले साल उनपर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई थी। वहीं इसी साल सितंबर में खेली गई यूपी क्रिकेट लीग में उन्होंने सबसे अधिक 22 विकेट झटके। इसके लिए महज उन्होंने 10 मुकाबले खेले। शहर के हर्ष अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं वह रेलवे की ओर से रणजी सहित अन्य घरेलू प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं। वर्तमान में वह दिल्ली टीम का हिस्सा हैं।

ध्रुव राजस्थान और भुवनेश्वर बेंगलुरु की टीम में खेलेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी ध्रुव जुरेल को राजस्थान रॉयल ने रीटेन किया है। उन्हें 14 करोड़ में रिटेन किया गया है। वह भारतीय टेस्ट टीम के नियमित खिलाड़ी हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक शतक भी लगाया था। वह उत्तर प्रदेश घरेलू प्रतियोगिताएं खेलते हैं। भुवनेश्वर कुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा हैं। वह दो वर्ष से ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं।

दीपावली का यूनेस्को की धरोहर में शामिल होना हर भारतीय के लिए गौरव: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दीपावली को यूनेस्को सूची में शामिल किये जाने का किया स्वागत

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए इसे भारत के सभ्यतागत मूल्यों की ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता बताया। गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है और ''भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण'' है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में दिल्ली इस वर्ष 'भव्य दीपावली' मनायेगी। उन्होंने कहा, ''अब दुनिया दीपावली के बारे में और अधिक गहराई से जानेगी। हर राज्य इस पल को गर्व से मनायेगा। सभी को बधाई।

गुप्ता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की ''विकास भी, विरासत भी'' की यात्रा को दर्शाता है। उन्होंने लिखा, ''एक ऐसा त्योहार जो हमारे घरों और दिलों में बसता है, आज विश्व द्वारा साझा किए गए सांस्कृतिक खजाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत की सभ्यतागत विरासत को ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता मिल रही है।'' गुप्ता ने इसे ''वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम अध्याय'' बताते हुए कहा कि भारत की सनातन परंपराओं की सार्वभौमिकता को विश्व के सर्वोच्च सांस्कृतिक मंच पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, ''दीपावली महज एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रकाश है जो सदियों से मानवता को सत्य, आशा और नैतिकता के पथ पर अग्रसर करता आया है।''

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ''इस ऐतिहासिक फैसले का खुशी से स्वागत करती है।'' गुप्ता ने यूनेस्को और उन परिवारों, कारीगरों और भक्तों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस त्योहार की परंपराओं को संरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ता है, इससे पहले योग, कुंभ, दुर्गा पूजा और गरबा को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इस वर्ष एक विशेष 'भव्य दीपावली' समारोह के साथ इस अवसर को मनाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को बल मिलेगा।

यूनेस्को ने दीपावली को घोषित किया 'विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर', भाजपा में जश्न का माहौल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में चल रहे यूनेस्को के सेशन में बुधवार को भारतीय त्योहार दीपावली को विश्व धरोहर घोषित किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से पूरे सनातन समाज में खुशी की अनुभूति हो रही है। अब हर भारतीय सनातनी का फर्ज है कि दीपावली सदा एक जीवंत त्योहार के रूप में मने। सचदेवा ने कहा कि दीप जगा कर हर ओर स्वच्छता के साथ रोशनी बिखेर कर लक्ष्मी पूजन का पर्व दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे कश्मीर से कन्या कुमारी तक पूरा देश एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाता है। सचदेवा ने कहा कि दीपावली समाज में खुशियां बांटने का पर्व है, यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने परिजनों एवं मित्रों के साथ ही कर्मियों और जरूरतमंदों को उपहार देकर खुशियां बांटते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस उपलक्ष्य में जब भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार सभी अपने कार्यालयों को आज सांयकाल सजा रहे हैं जगमगा रहे हैं। ऐसे में हमने दिल्ली भाजपा कार्यालय को भी आज सांय से दो दिन सजाने जगमगाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार और आईओसीएल के बीच हुआ एमओयू साइन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में बुधवार को दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर साइन किया गया। यह समझौता दिल्ली सचिवालय में हुआ। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह समझौता फ्लाईओवरों के सौन्दर्यीकरण, चिकित्सा उपकरणों के प्रावधान, वाटर एटीएम की उपलब्धता, ऊर्जा केंद्रों की स्थापना और बसों की ब्रांडिंग के माध्यम से दिल्ली को एक सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित राजधानी में बदलने की दिशा में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यटन को बढ़ावा देने, शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली में बड़े बदलाव हो रहे: सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राजधानी की वैश्विक छवि का पुनर्निर्माण करने और पर्यटन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि काफी समय से लंबित व्यवस्थागत समस्याओं का समन्वित शासन के माध्यम से अंततः समाधान किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि 'विकसित दिल्ली, विकसित पर्यटन' की परिकल्पना दिल्ली को ऐसी विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में स्थापित करने की सरकार की नयी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो पर्यटकों में भरोसा पैदा करती हो। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से स्वीकृतियों की बहुलता जैसी पुरानी समस्याओं ने दिल्ली की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को धीमा कर दिया था, लेकिन शासन में बेहतर तालमेल के कारण अब ये बाधाएं दूर हो रही हैं।

गुप्ता ने यहां एक शिखर सम्मेलन में मीडिया से कहा, ''आज हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं क्योंकि भाजपा तीनों स्तरों पर सरकार में है। इस मुकाम तक पहुंचने में हमें 27 साल लग गए। हमारे पास लंबे समय से चली आ रही कठिनाइयों को दूर करने का अंततः अब अवसर है।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ''लोगों और व्यवस्था की समस्याओं को पूरी तरह समझते हैं।'' गुप्ता ने हाल में हुए प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने प्रतिष्ठानों के लिए पुलिस लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं और वह अब तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से अग्नि सुरक्षा लाइसेंस जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य एकाधिकार को समाप्त करना और देरी को कम करना है। उन्होंने कहा, ''हम व्यवस्था को सरल बनाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि व्यवसाय और पर्यटन क्षेत्र अनावश्यक बाधाओं के बिना विकसित हो सकें।

बांसुरी स्वराज ने आरके पुरम में सुरक्षा गार्डों को वितरित किए इलेक्ट्रिक हीटर

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज ने बुधवार को आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा गार्डों को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित की। इस कार्यक्रम का आयोजन विधायक अनिल शर्मा ने किया। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह पहल उन सुरक्षा कर्मियों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है, जो दिन-रात हमारी कॉलोनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा शुरू किए गए उस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुरी दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सुरक्षा कर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर से न केवल गार्डों को कड़ाके की ठंड में राहत मिलेगी, बल्कि खुली आग जलाने की आवश्यकता कम होने से वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि इस जनहितकारी पहल के सुचारू संचालन में अधिकारियों ने पूरा सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंदर चौधरी और दिल्ली सरकार के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि, दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तीन हजार से ज्यादा आरडब्ल्यूए, सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराने की बात की थी।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के तीन स्कूलों को मिली बम की धमकी फर्जी पायी गई

नई दिल्ली। दिल्ली के तीन निजी स्कूलों में बुधवार सुबह बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद तुरंत आपातकालीन कार्रवाई की गई और स्कूलों को खाली करा लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाद में इसे बम की धमकी को 'फर्जी' घोषित कर दिया गया क्योंकि कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अधिकारी ने लक्ष्मी नगर स्थित लवली पब्लिक स्कूल के नाम की पुष्टि की, जबकि पुलिस ने कहा कि सादिक नगर स्थित द इंडियन स्कूल और आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी इसी तरह की धमकियां मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल सुबह करीब 10 बजे प्राप्त हुए, जिनमें दावा किया गया था कि स्कूलों के अंदर एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया है। सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों को भेज दी गई। दमकल गाड़ियां, बम निरोधक दस्ते, खोजी कुत्ते और पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर भेजी गईं। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। एक अधिकारी ने बताया, ₹अभी तक किसी भी संदिग्ध चीज का पता नहीं चला है। बम की धमकी को 'झूठी धमकी' घोषित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के छह आरोपितों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान ने जमानत याचिका दायर की हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि आरोपितों ने साजिश रची थी कि देश की सत्ता को पलटा जाए और नेपाल और बांग्लादेश की तरह सत्ता के खिलाफ बगावत करना चाहते थे। केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि आरोपितों के मन में संविधान के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं बचा है और वे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में डंडे, एसिड की बोतलें और आग्नेयास्त्र लेकर चलते थे। राजू ने कहा था कि आरोपितों को केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि ट्रायल में देरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि ट्रायल में देरी आरोपितों की वजह से हो रही है ना कि अभियोजन पक्ष की वजह से। आरोपित उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में 751 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन उमर खालिद का नाम केवल एक एफआईआर में है। उसमें दिसंबर, 2022 में बरी कर दिया गया। एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें साजिश का जिक्र है। सिब्बल ने कहा था कि 750 एफआईआर में उमर खालिद किसी में भी लिप्त नहीं है।

पुलिस ने खोए हुए 625 फोन उनके मालिकों को लौटाए

नई दिल्ली। शाहदरा जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत इस साल चोरी, झपटे और लूटे गए 625 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा है। शिकायत मिलने के बाद जिले की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इन सभी मोबाइल फोन को दिल्ली, उप्र, बिहार, मध्य प्रदेश व पंजाब से बरामद किया है। बाद में इन सभी मोबाइल फोन को अलग-अलग दिन पुलिस उपायुक्त कार्यालय में कार्यक्रम कर उनके मालिकों के हवाले कर दिया। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम का कहना है कि उनका ऑपरेशन जारी है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस साल 1 मई को ऑपरेशन विश्वास की शुरुआत की गई थी। इसके तहत खोए हुए, चोरी, लूटे और छीने गए मोबाइल फोन को शिकायत के बाद ट्रेस करने का बीड़ा उठाया गया। जिले में टेक्निकल सर्विलांस टीम का गठन किया गया। टीम ने शिकायतों के आधार पर उनको ट्रेस करना शुरू किया। सबसे पहले सीडीआर और आईएमईआई नंबर के आधार पर फोन की तलाश शुरू की। इसके लिए केंद्र सरकार के सीईआईआर पोर्टल की मदद ली गई।

इसके तहत खोए हुए 321, चोरी हुए 202, घर में हुई चोरी में गायब 39, झपटमारी के 61 और लूटे गए 2 मोबाइल फोन को बरामद किया गया।

लोकल पुलिस ने इसके लिए पूरी मदद की। पिछले साल के आंकड़े पर गौर करें तो वर्ष 2024 में 555 और वर्ष 2023 में इसी तरह 205 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि हालांकि गायब हुए ज्यादातर मोबाइल फोन को विदेश ठिकाने लगा दिए जाते हैं। भारत में भी फोन एक्टिवेट हैं या कोई बदमाश मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है कि उससे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस साल मोबाइल की तलाश के दौरान टीम ने 526 मोबाइल फोन दिल्ली से बरामद किए हैं। इसके अलावा उप्र से 90, बिहार से 6 और पंजाब व एमपी से 1-1 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली से बरामद मोबाइल फोन का ब्रेकअप देखा जाए तो विवेक विहार से 33, आनंद विहार से 26, जगतपुरी से 15, गांधी नगर से 11, कृष्णा नगर से 19, गीता कालोनी से 17, शाहदरा से 39, फर्श बाजार से 54, मानसरोवर पार्क से 25, सीमापुरी से 165 और जीटीबी एंक्लेव से 221 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष अभियान शुरू

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से बुधवार को दिल्ली के सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर केंद्रित एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान दिसंबर से जनवरी तक विभिन्न मेट्रो ट्रेनों और चयनित स्टेशनों में व्यापक जागरूकता गतिविधियों के रूप में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन, पीसी एवं पीएनडीटी कानून, और टीबी उन्मूलन जैसे अहम विषयों पर संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि रोजाना मेट्रो का उपयोग करने वाली लाखों महिलाएं और लड़कियां इन महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत हो सकें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का उपयोग इन संदेशों को तेजी से और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल जागरूकता बढ़ेगी बल्कि शहर भर में महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में यात्रियों के बीच स्वास्थ्य-संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद बढ़ाना और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, जागरूक और सहयोगी वातावरण तैयार करना है।

द्वारका कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर विकास लगरपुरिया व साथी को मकोका में दोषी ठहराया

❖ जनभावना टाइम्स

- दिल्ली-हरियाणा में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, फिरौती और अपहरण सहित 24 से अधिक मामले हैं दर्ज
- आजीवन कारावास तक की सजा संभव, 13 दिसंबर को होगी बहस

नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के खूंखार गैंगस्टर विकास गुलिया उर्फ विकास लगरपुरिया और उसके करीबी साथी धीरपाल उर्फ काना को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धारा-3 (संगठित अपराध में संलिप्तता) के तहत दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (मकोका) वंदना जैन की अदालत ने नजफगढ़ थाने में 2015 में दर्ज FIR संख्या 531/2015 के तहत दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया।

हालांकि दोनों आरोपियों को मकोका की धारा-4 (संगठित अपराध सिंडिकेट की बेनामी संपत्ति रखना) के आरोप से बरी कर दिया गया। बुधवार को दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। विकास लगरपुरिया को मंडोली जेल-14 से जबकि धीरपाल उर्फ काना को रोहिणी जेल-10 से पेश किया गया। उनकी ओर से पैरवी करने वाले नियमित वकील अनिरुद्ध यादव की जगह प्रॉक्सी काउंसिल शारिक मिर्जा, विनीत और अनुज मौजूद रहे।

कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए मामले को 13 दिसंबर 2025 की तारीख दे दी है। साथ ही दोनों जेलों के अधीक्षकों से आरोपियों का नॉमिनल रोल (जेल में आचरण रिपोर्ट) भी तलब किया गया है। विकास लगरपुरिया पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण और फिरौती सहित 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 2021 में गुरुग्राम में हुए बहु-करोड़ी लूटकांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है।

2022 में दुबई से गिरफ्तार कर उसे भारत लाया गया था।धीरपाल उर्फ काना मनोज मोरखेरी-लगरपुरिया गैंग का सक्रिय शूटर है। छावला डबल मर्डर केस सहित कई संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे फरवरी 2025 में धर दबोचा था। मकोका की धारा-3 में दोषी ठहराए जाने पर न्यूनतम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दोनों गैंगस्टरों की सजा पर अंतिम फैसला 13 दिसंबर को बहस पूरी होने के बाद आएगा।

मंत्री आशीष सूद ने सफाई व्यवस्था व कूड़ा प्रबंधन कार्यों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को वार्ड संख्या 108, हस्तसाल में रोड संख्या 237, होली चौक, हस्तसाल, उत्तमनगर और विकासपुरी स्थित डीएवी स्कूल क्षेत्र में साफ सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, कूड़ा प्रबंधन, नालों की साफ-सफाई आदि कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मंत्री को बताया की विकासपुरी के डीएवी स्कूल के सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है जिससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है बल्कि इस कूड़े से यहां प्रदूषण भी हो रहा है। इसके साथ ही रोड नंबर 237 पर कई जगह सीवरों के ढक्कन खुले हुए हैं जिनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही रोड के ऊपर कई जगह कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और उसको उठाने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

निरीक्षण के बाद शहरी विकास मंत्री ने बताया कि दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में लोगों को स्वच्छता सेवाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से उपलब्ध करना सरकार का लक्ष्य है। हरेक इलाके में नियमित रूप से साफ-सफाई और कूड़े का प्रबंधन किया जाए। इसी कड़ी में आज विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया गया ताकि जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकें।

मंत्री सूद ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में चल रहे सफाई एवं स्वच्छता कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के साथ कूड़ा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी, नालों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम को हर संभव सहयोग देकर राजधानी की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच वर्षों से चली आ रही खींचातानी अब समाप्त होनी चाहिए। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी बंद होना आवश्यक है।

मंत्री ने यह भी कहा कि जब दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच मजबूत इंट्रा-डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा तभी हम विकसित दिल्ली के संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता केवल नगर निगम या सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों के सहयोग से चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जिसमें सभी का साथ सहयोग चाहिए। शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा की इन कार्यों को करने वाली सभी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की शिकायतों के शीघ्र अति शीघ्र समाधान पर गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है।

संपादकीय

किराएदार के अधिकारों का संरक्षण

यह सोच अपने-आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो। भारत सरकार का कहना है कि मकान किराया संबंधी नए नियमों में उसने मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। चूंकि अब मकान किराए पर देने से संबंधित दस्तावेज का 60 दिन के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसलिए समझा जा सकता है कि नए नियमों का मकसद टैक्स वसूली को सुनिश्चित करना भी है। बहरहाल, यह सोच अपने-आप में सही जगह पर है कि मकान किराए पर लगाने का कारोबार औपचारिक दायरे में आए और जहां अपने मकान की सुरक्षा को लेकर मालिक आश्वस्त हों, वहीं किराएदार के अधिकारों का भी संरक्षण हो।

तो प्रावधान किया गया है कि मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, सुरक्षा जमा (डिपॉजिट) की सीमा तय कर दी गई है और किराया वृद्धि को भी नियमित किया गया है। आवासीय मकसद के लिए किराए पर लगाए गए मकान के मालिक अब दो महीने से अधिक का डिपॉजिट नहीं ले सकेंगे। खासकर बड़े शहरों में चलन छह महीने या सालभर का एडवांस किराया लेने का रहा है। साथ ही मकान मालिक अब अचानक किराया नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए उन्हें पहले से नोटिस देना होगा। इसी तरह मकान मालिक अब किसी किरायेदार को अचानक घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निश्चित नोटिस पीरियड और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

किराएदार किसी मरम्मत के लिए शिकायत करता है, तो मकान मालिक को ऐसा 30 दिन के अंदर कराना होगा। वरना, किराएदार को अधिकार होगा कि वह खुद मरम्मत करवा कर आए खर्च को किराए में एडजस्ट कर ले। उधर चूंकि किराएदारी के हर समझौते का डिजिटल स्टांप करवा कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तो उससे मकान मालिकों को सुरक्षा मिलेगी। यह भी तय किया गया है कि संबंधित ट्रिब्यूनल को सभी विवादों का निपटारा 60 दिन के अंदर करना होगा। ये अच्छी पहल है। मगर, यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं उलझाऊ ना हों तथा इसे कराने की सारी जहमत किराएदारों को ही ना उठानी पड़े।

विकसित भारत का मूल मंत्र बनेगा 'वंदे मातरम्'

चर्चा का आरम्भ करते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम् के प्रति कांग्रेस व उनके नेताओं की सोच को बेनकाब कर दिया। सरकार ने वंदे मातरम् गीत की प्रेरणा से संकल्प लेकर वर्ष साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ राष्ट्रगीत को जीवंत बनाने का संकल्प लिया। वंदे मातरम् गीत की महानता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि `जो वंदे मातरम् साल 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप मे दिखता था, देश के हर कोने में हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जागता था, उन सबके लिए वंदे मातरम् की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम् इतना महान था, उसकी भावना इतनी महान थी तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ ? वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ ? वह कौन-सी ताकत थी जो महात्मा गांधी की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई ? किसने वंदे मातरम् जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। सदन को बताया गया कि जब वंदे मातरम् को 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने को मजबूर था।

-मृत्युंजय दीक्षित

जिससे स्वतंत्रता का मूल मंत्र, "वंदे मातरम्" उद्भासित हुआ, जिसे गाते हुए हजारों की संख्या क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल गए, जीवन जेलों की क्रूर यातनाओं में काट दिया, जिस गीत ने माँ भारती के प्रति प्रेम और समर्पण को परिभाषित किया, जिस गीत ने स्वाधीनता की अलख संपूर्ण भारत में जगा दी वह गीत है राष्ट्रगीत- वंदे मतारम। भारत विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में बंग-भंग के अंग्रेजी षड्यंत्र को पहचान कर सम्पूर्ण राष्ट्र बंगाल विभाजन के विरुद्ध खड़ा हो गया। इस आंदोलन के दो हथियार थे- स्वदेशी का स्वीकार-विदेशी का बहिष्कार और रणघोष बना था वंदे मातरम्। इस गीत के रचनाकार थे बंगाल में जन्मे महान सपूत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आज वंदे मातरम् अपनी रचना का 150 वां वर्ष मना रहा है।

इस अवसर पर वंदे मातरम् गीत के माध्यम से एक बार पुनः राष्ट्र में "स्व" की भावना की अलख जगाने का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम् पर व्यापक चर्चा हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने जहां वंदे मातरम् गीत के इतिहास और उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वंदेमातरम् के प्रति कांग्रेस व वामपंथी दलों की विचारधारा और सोच को बेनकाब किया। विपक्ष ने इसके पीछे बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई चर्चा बताया। कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि वंदे मातरम् पर बहस गैरजरूरी और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। इतने गंभीर व ऐतिहासिक विषय की बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से गायब रहे। संसद

में वंदे मातरम् पर हुई व्यापक चर्चा सिर्फ एक गीत पर विमर्श नहीं वरन भारत की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को दोबारा केंद्र में लाने का प्रयास भी है।

चर्चा का आरम्भ करते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम् के प्रति कांग्रेस व उनके नेताओं की सोच को बेनकाब कर दिया। सरकार ने वंदे मातरम् गीत की प्रेरणा से संकल्प लेकर वर्ष साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ राष्ट्रगीत को जीवंत बनाने का संकल्प लिया। वंदे मातरम् गीत की महानता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि `जो वंदे मातरम् साल 1905 में महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप मे दिखता था, देश के हर कोने में हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जागता था, उन सबके लिए वंदे मातरम् की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम् इतना महान था, उसकी भावना इतनी महान थी तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात क्यों हुआ ? वह कौन-सी ताकत थी जो महात्मा गांधी की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? किसने वंदे मातरम् जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। सदन को बताया गया कि जब वंदे मातरम् को 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने को मजबूर था और जब वंदे मातरम् के 100 वर्ष पूर्ण हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस वंदे मातरम् ने देश को आजादी की नई ऊर्जा दी थी जब उसके 100 वर्ष हुए तो दुर्भाग्य से एक काला इतिहास हमारे कालखंड में उजागर हो गया।'

प्रधानमंत्री ने बताया कि `वंदे मातरम् के प्रति मुस्लिम लीग के विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्तूबर 1937 को वंदे मातरम् के विरुद्ध नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा तो उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देने के बजाय वंदे मातरम् की ही पड़ताल शुरू कर दी और कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी में वंदे मातरम् की उपयोगिता पर चर्चा होगी। इससे पूरा देश हतप्रभ रह गया। देशभक्तों ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव के खिलाफ देश के कोने-कोने में प्रभात फेरियां निकाली और वंदे मातरम् गीत गाया किन्तु देशभक्तों को अनसुना करते हुए 26 अक्टूबर 1937 को कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर समझौता कर लिया।'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जैसा सम्मान मिलने की बात कही। राजनाथ सिंह ने यह धारणा तोड़ने का प्रयास किया कि वंदे मातरम् किसी सांप्रदायिक विचार का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कुछ कट्टरपंथियों ने जानबूझकर इसे धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की जबकि यह गीत भारत माता के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता की पुकार का प्रतीक है।

राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के साल 1937 के अधिवेशन में वंदे मातरम् के अंतिम चार छंदों का गायन रोके जाने के प्रस्ताव पर बात की और पंडित नेहरू की भूमिका पर प्रश्न उठाए। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि संसद में जब भी वंदेमातरम् का गायन होता है तब कई विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं। वंदे मातरम् पर चर्चा की आवश्यकता पर उत्तर देते हुए अमित शाह ने कहा कि `वंदे मातरम् पर चर्चा की आवश्यकता जब वंदे मातरम् रचा गया था तब भी थी, आजादी के समय मे भी थी, आज भी है और साल 2047 में जब आधुनिक भारत होगा तब भी रहेगी क्योकि वंदे मातरम् में कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की भावना है।' गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि `जिस पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम् गाकर कराते थे उस पर जब लोकसभा में चर्चा हुई तो गांधी परिवार के सदस्य सदन में नहीं थे। नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने वंदे मातरम् गान का विरोध किया है। भविष्य में वंदे मातरम् देश को विकसित और महान बनाने का उद्घोष बनेगा।'

वंदे मातरम् गीत ने राष्ट्र की सोई हुई को चेतना को जागृत किया और देशवासियों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया। आज आत्मनिर्भर भारत विकसित बनाने के लिए उसी वंदे मातरम् के भाव का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है। वंदे मातरम् भारतवासियों के हृदय के तारों को झंकृत करे और प्रत्येक भारतीय प्राणपण से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के यज्ञ में कूद पड़े, यही वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ मनाने की सार्थकता होगी।

हिंदू विकास दर: भारत के साथ अमेरिका और यूरोप के आर्थिक विकास में भी अहम योगदान

-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

आज़ादी के बाद से नेहरूवादी नीति ने भारत को आर्थिक विकास के लिए हिंदू दृष्टिकोण के बजाय समाजवादी विकास मॉडल अपनाने पर मजबूर किया था। इस रणनीति के अनुसार, निजी उद्यमशीलता कठोर लाइसेंस राज के अधीन थी, जिसने केवल लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभानी थी। इस कम्युनिस्ट, केंद्रीय रूप से नियोजित आर्थिक मॉडल द्वारा निजी निवेश की भूमिका सीमित कर दी गई। अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में इस प्रतिमान ने वर्षों तक सपाट या खराब जीडीपी विकास दरें पैदा कीं और भारत को गरीबी से बाहर निकालने में विफल रहा। दशकों की कम विकास दरों की भारी विफलता के बारे में पूछे जाने पर कहानी- या बल्कि स्पष्टीकरण- देश के हिंदुओं को बदनाम करने और दोष देने का था।

'हिंदू विकास दर' शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के लिए किया था, जो साल 1960 और 1980 के दशक के दौरान औसतन लगभग 4% थी। इसका मतलब यह दिखाना था कि आज़ाद भारत की समाजवादी नीतियों के शुरुआती दशकों के दौरान देश की हिंदू आबादी धीमी प्रगति से कैसे जूझ रही थी। आज के समय में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है और अपनी पुरानी शान हासिल करने के लिए तैयार है। अर्थशास्त्री इस कुख्यात और भ्रामक कहावत का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं और अर्थशास्त्र के छात्रों को इसे पूरे देश में सीखना पड़ता है। यह चतुर शब्द एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री द्वारा जानबूझकर हिंदू समाज को आर्थिक गतिविधि के मामले में ऐतिहासिक रूप से अविकसित के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयास में गढ़ा गया था।

चूंकि नरेन्द्र मोदी प्रशासन के तहत भारत उपनिवेशवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है इसलिए इस कलंकित करने वाले शब्द को खत्म करने की ज़रूरत है। नेहरूवादी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ी। अक्सर जनसंख्या वृद्धि दर से कम। नतीजतन, पश्चिमी देशों ने हमारी विकास गति का मज़ाक उड़ाया, जो हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर से तेज़ नहीं थी। 'हिंदू' विशेषण हमारे हिंदू समुदाय को पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित मुक्त बाज़ार के बजाय समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए बदनाम करने के लिए जोड़ा गया था। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत से लेकर भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। 300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग मौर्य साम्राज्य द्वारा एकजुट हो गया था, जिससे व्यापार और वाणिज्य में सुधार हुआ, कृषि उत्पादन बेहतर हुआ और सुरक्षा बढ़ी। 1 से 1000 ईस्वी के बीच भारत का वैश्विक जीडीपी में 30% हिस्सा था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में औद्योगीकरण में गिरावट आई और कई शिल्प और अन्य उद्योग खत्म हो गए। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन 1750 में 25% से गिरकर 1900 में 2% हो गया और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका अनुपात 1700 में 24.4% से गिरकर 1947 में 3% हो गया। ब्रिटेन द्वारा भारत के शोषण से ही उसके 200 साल के विकास के लिए धन मिला।

इसे समझने के लिए मात्रात्मक मैक्रोइकोनॉमिक इतिहास में विशेषज्ञता वाले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'एंगस मैडिसन' के काम का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। उनका सबसे प्रसिद्ध अध्ययन, 'द वर्ल्ड इकोनॉमी- ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव,' जिसे OECD संगठन द्वारा जारी किया गया था, उसने पश्चिम को तब चौंका दिया जब इसमें प्राचीन और आधुनिक वैश्विक इतिहास दोनों में भारत के आर्थिक प्रभुत्व का पता चला। एंगस मैडिसन के शोध के अनुसार, भारत का जीडीपी दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 30% था। तुलनात्मक कीमतों और विनिमय दरों में संभावित बदलावों को ध्यान में रखने के लिए अनुमानों में क्रय शक्ति समता दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। पश्चिमी यूरोप, जिसमें पूर्व रोमन क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल है, उसका बाजार में लगभग 11% हिस्सा था। यह अविश्वसनीय लगता है, खासकर यह देखते हुए कि सदियों के आक्रमणों और विदेशी कब्ज़े को रोकने के लिए भारतीय पीढ़ियों द्वारा किए गए संघर्षों के कारण हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कितना कम जानते हैं। फिर भी, अगर हम समय और प्राचीनता में बड़ी दूरी के कारण अनुमानों को नज़रअंदाज़ करें तो यह वास्तव में एक अद्भुत काम है। एंगस मेडिसन के लेखों में भारतीय व्यापारियों के प्रभुत्व पर भी चर्चा की गई है, जो पूरे मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया में काम करते थे, साथ ही भारत के साथ अपने देश के चालू खाते के असंतुलन (घाटे) के बारे में रोमन अधिकारियों की शिकायतों पर भी। इसका श्रेय हिंदू अर्थशास्त्र या जिसे कुछ लोग 'तीसरा रास्ता' कहते हैं, उसको दिया जा सकता है। पहले का श्रेय डॉ. एम.जी. बोकारे को दिया जाता है, जबकि बाद वाला दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा बनाया गया था। बोकारे का दावा है कि पवित्र वेद, जो बाज़ार, आपूर्ति, मांग और अन्य आर्थिक अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं, हिंदू अर्थशास्त्र में समाहित हैं।

संक्षेप में, पारंपरिक पूंजीवाद या मार्क्सवाद के पश्चिमी प्रतिमान को इस तीसरे रास्ते से खारिज कर दिया जाता है। यह किसी भी कीनेसियन विचारों या एडम स्मिथ के दृष्टिकोण का पालन नहीं करता है। इस स्थिति का दिलचस्प पहलू यह है कि बोकारे और ठेंगड़ी वैचारिक रूप से एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। फिर भी, दोनों का मानना था कि लोकतंत्र और हिंदू आर्थिक प्रणाली सामंजस्य में हैं। बोकारे ने तो इस बारे में भी लिखा है कि पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के शुरुआती संपर्क ने भारतीयों को कैसे प्रभावित किया है। मार्क्सवादी या कीनेसियन अर्थशास्त्र की तरह हिंदू अर्थशास्त्र को भी कई लोग अर्थशास्त्र के एक अलग स्कूल के रूप में देखते हैं। विकास के पश्चिमी मॉडल की कमियों को कई पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। सोवियत संघ के पतन और अमेरिका और यूरोप की बिगड़ती स्थिति ने दिखाया है कि पूंजीवाद और मार्क्सवाद के विकास मॉडल अपर्याप्त हैं। कई लोगों का मानना है कि पश्चिम आर्थिक और अन्य दोनों तरह से शक्ति संतुलन खो रहा है। हिंदू सोच पर आधारित शासन के पिछले 11 वर्षों में अपने कई उत्कृष्ट उपायों के कारण भारत इस मामले में आगे है। आत्मनिर्भर भारत विज़न के तहत घरेलू सुधारों और ग्लोबल पोजीशनिंग की वजह से हिंदू विचारधारा वाली सरकार के तहत साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। रियल GDP 6.5% की दर से बढ़ रहा है और नॉमिनल GDP 106.57 लाख करोड़ रुपये (2014-15) से तीन गुना बढ़कर 331.03 लाख करोड़ रुपये(2024-25) हो गया है, जिससे भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। जर्मनी का नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद अभी USD 4.6 ट्रिलियन है और यह सामान्य दर से बढ़ रहा है। इसलिए, भारत 2026-2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जर्मनी को पीछे छोड़ने के बहुत करीब होगा।

इन लोगों को खिलाएं खाना, रहेगी स्थिर लक्ष्मी

हमारें जीवन में कई उतार चढ़ाव आते है जिससे की लोग बहुत दुखी होते है और कुछ लोग उस समस्या का निजात निकाल कर उससे निकल जाते है। इस दुनिया में बहुत कम लोग है जो अपने जीवन से खुशी है। किसी न किसी को की न कोई समस्या है। अमीर के पास धन होते हुए भी और धन की ललसा और एक गरीब के पास धन न होते हुए सिर्फ पेट की भुख मिटाने तकी ललसा। हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या नही करते है। तरह-तरह के उपाय अपनाते है जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाएं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कई ऐसे उपाय बताए गें है जिनका आमरण करे तो हम सफलता ही हर ऊचांई को छूते चले जाएगे। शास्त्रों में दी गई बातें हमें कभी निराश नही कर सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में भोजन के बारें में की बातें बताई गई है।

धर्मकर्म

गाय को खिलाएं रोटी- हिंदू धर्म में गाय को माता समान माना जाता है। यह पुज्नीय भी है। हमारें शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम खाना बनाएं उसके बाद सबसे पहले एक रोटी गाय को खिलाएं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को रोटी या हरी घास रोज खिलाता है तो उसे जल्द ही कोई अच्छा फल मिलता है साथ ही कई गुना पुण्य भी मिलता है। साथ ही कुंडली में लगे कई दोष ही शांत हो जाते है। और घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए एक रोटी जरुर खिलाना चाहिए।

कुत्तें को खिलाएं रोटी- अगर आपको अपने शत्रु का भय सता रहा हो जिसके कारण आप उससे डर कर रह रहे है। तो रोज एक रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे आपका शत्रु का भय खत्म हो जाएगा। और आप निडर हो कर रह सकेगे। साथ ही अगरा पकी कुंडली में शनि का दोष है तो शिवार के दिन काले रंग के कुत्तें को रोटी खिलाएं। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगा। और शनि दोष शांत होगा। माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए आ जाएगी।

मछली को खिलाएं आटे की गोली- शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपकी पुरानी संपत्ति हाथ से निकल गई हो या फिर कोई मुल्यवान चीज खो गई हो तो रोज तालाब या नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी पुरानी संपत्ति वापस मिल जाएगी।

आज का इतिहास

- 1687 - ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास (भारत) में नगर निगम बनाया।
- 1845 - प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध शुरू।
- 1858 - बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने।
- 1937 - यूरोपीय देश इटली मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया।
- 1941 - जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनिटो मुसोलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की।
- 1946 - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
- 1946 - यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया।
- 1946 - संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई।
- 1949 - खाशाबा जाधव - नागपुर की कुश्ती स्पर्धा में प्रतिस्पर्धी को मात्र पांच मिनट के भीतर ही चित कर दिया।
- 1960 - बाल विकास में लगी अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में भी 15 नये पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया।
- 1983 - जनरल एच.एम. इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।
- 1994 - रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया तथा उनके इलाके में सेना भेज दी।
- 1997 - ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत।
- 1998 - 23वें काहिरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म 'टेररिस्ट' सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 2002 - स्पेन के नौसैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज़ को पकड़ा, इसमें स्कड मिसाइलें लदी थीं।
- 2003 - मेरिदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किये।
- 2007 - उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारम्भ।
- 2014 - अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी।

बच्चों के भविष्य की रोशनी जगाता यूनिसेफ

यूनिसेफ स्थापना दिवस पर विशेष

- योगेश कुमार गोयल

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 दिसम्बर 1946 को न्यूयार्क में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। उस समय इसे 'यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड' के नाम से जाना जाता था। विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विस्तारित किया गया। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से 'अंतरराष्ट्रीय' तथा 'आपातकालीन' (इमरजेंसी) शब्दों को हटा दिया गया। 1953 में यूनिसेफ के संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाने के बाद इसका नाम 'यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड' (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) कर दिया गया लेकिन मूल संक्षिप्त नाम 'यूनिसेफ' को बरकरार रखा गया। यूनिसेफ के गठन में पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉश्मन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने तथा उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने का दायित्व यूनिसेफ को सौंपा गया है, जो बाल अधिकार समझौते से मार्गदर्शन लेते हुए बाल अधिकारों को चिरंतन नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने के लिए सदैव प्रत्यनशील रहता है। अपनी स्थापना के बाद के इन 79 वर्षों में यूनिसेफ ने दुनियाभर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विश्वभर में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तथा वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तुरियस अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है।

नोबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ का कार्य और तेज हो गया। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यूनिसेफ की शिक्षा इकाई के कारण ही वर्ष 2006 तक विश्वभर में करीब 12 मिलियन बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल वापस जा सके। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए यूनिसेफ आपात स्थितियों में कार्रवाई करता है और युद्ध, आपदा, घोर गरीबी, हर प्रकार की हिंसा और शोषण तथा विकलांगता से पीड़ति सर्वाधिक वंचित बच्चों के लिए विशेष संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। यह बच्चों को पहला अधिकार दिलाता है और वंचित बच्चों तथा उनके परिवारों के लिए उपयुक्त नीतियां बनवाने और सेवाएं प्रदान करने की देशों की क्षमता का निर्माण करता है।

1946 में यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय युद्ध में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से ही की गई थी लेकिन अब यह संस्था दुनियाभर में बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत है। वर्तमान में यूनिसेफ के कार्यकर्ता दुनियाभर के 190 से भी अधिक देशों में बच्चों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं। भारत में इस संस्था ने वर्ष 1949 में कार्य करना प्रारंभ किया था और अब हमारे यहां यह नई दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में कार्य कर रही है।

बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, बाल पर्यावरण, पोलियो उन्मूलन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, बच्चे और एड्स, सामाजिक नीति, नियोजन, निगरानी एवं मूल्यांकन, हिमायत और भागीदारी, आचरण परिवर्तन संदेश, आपात स्थिति तैयारी और कार्रवाई जैसे क्षेत्रों पर यूनिसेफ का मुख्य फोकस रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग के अलावा यूनिसेफ द्वारा दुनियाभर में मौजूद अनेक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इंफेक्शंस आदि के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दुनियाभर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए तीन बिलियन से भी अधिक टीके प्रदान किए जाते हैं।

यूनिसेफ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह संस्था दुनियाभर में बच्चों के कल्याण हेतु कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। यह संस्था 49 से भी अधिक देशों में एचआईवी/एड्स से बचाव की लड़ाई में निरन्तर कार्यरत है।

यूनिसेफ का 36 सदस्यों का कार्यकारी दल इसके कार्यों की देखरेख करता है, इसकी नीतियां बनाता है तथा यूनिसेफ के वित्तीय एवं प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों अथवा क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालय, मुख्यालय और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालय तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करते हैं। सात क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार सभी देशों में स्थित कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्वस्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। इस संस्था का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों तथा निजी दानदाताओं द्वारा किया जाता है। संस्था के संसाधनों का दो-तिहाई योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं और शेष योगदान निजी समूहों तथा व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। यूनिसेफ के लक्ष्यों की एक लंबी सूची है, जिसमें न्यूनतम-लागत हस्तक्षेप के माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन को बचाने, बच्चों के अवैध व्यापार और शोषण को रोकने तथा मां-बच्चे के बीच एचआईवी/एड्स के संक्रमण को समाप्त करने में सहायता करना शामिल हैं।

अनुमान लगाया जाता रहा है कि यूनिसेफ के राजस्व का करीब 92 फीसदी हिस्सा सेवा कार्यक्रमों के लिए वितरित कर दिया जाता है। वर्तमान में यूनिसेफ द्वारा बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा सहित लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी/एड्स, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष इत्यादि के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। यूनिसेफ इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चों का पोषण और देखभाल करना मानव प्रगति की आधारशिला है और उसका मानना है कि अगर दुनिया में फैली असमानता को मिटाया नहीं गया तो वर्ष 2030 तक लगभग 167 मिलियन बच्चे भीषण गरीबी में जीवन जीने को मजबूर होंगे। दरअसल माना जा रहा है कि 2030 तक पांच वर्ष से कम आयु के करीब 19 मिलियन बच्चों की विभिन्न कारणों से मौत हो जाएगी और करीब 60 मिलियन बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध ने इन चुनौतियों को और बढ़ाया है। ऐसे में बच्चों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत यूनिसेफ से उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं हो सकता : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भावना को मजबूत करती है।

राजधानी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति मूमू ने आयोग के हिंदी जर्नल नई दिशाएं और अंग्रेजी जर्नल जर्नल आफ द एनएचआरसी का वर्ष 2024- 25 का संस्करण जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी मूल भावना मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने मानवाधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अविभाज्य बताया था। राष्ट्रपति ने कहा कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। आयोग 3000 से अधिक मामलों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और विकास परस्पर जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाना मानवाधिकारों की पूर्ति का आधार है।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थानों ने वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है जिससे उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार मिला है। उन्होंने कहा कि हाल के श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकार और सुदृढ़ हुए हैं। सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है।

समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाते हैं मानवाधिकार : सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली। मानवाधिकार दिवस पर बुधवार को राज्य सभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में मानवाधिकारों की वैश्विक विरासत को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा का यह 77वां वर्ष है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी विश्वभर में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का बुनियादी स्तंभ बना हुआ है। इस वर्ष की वैश्विक थीम 'मानवाधिकारः हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएँ' का उल्लेख करते हुए सभापति ने कहा कि यह दिन तीन महत्त्वपूर्ण बातें याद दिलाती है, जिसमें मानवाधिकार को सकारात्मक, आवश्यक और सभी के लिए जरूरी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाते हैं, नुकसान को रोकते हैं और समुदायों को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश सदैव सार्वभौमिक मानवाधिकार मूल्यों का दृढ़ समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि मानवाधिकार प्रत्येक नागरिक– विशेषकर समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए वास्तविकता बनें। मानवाधिकार दिवस पर उन्होंने आह्वान किया कि हम पुनः संकल्प लें कि मानवाधिकारों को सभी के लिए सकारात्मक, आवश्यक और सुलभ बनाते हुए ऐसे राष्ट्र और विश्व का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन जी सके।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 160 स्टेशनों का हुआ पुनर्विकास : वैष्णव

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 160 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है।

प्रश्नकाल के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद से भाजपा के सदस्य गोडम नागेश के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़े प्रश्न पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में सात हजार से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, जिनका श्रेणीकरण फुटफॉल, ट्रेन आवागमन और व्यस्तता के आधार पर एनएसजी-1 से एनएसजी-6 तक किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन पुनर्निर्माण कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों पर पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जिनमें से 160 स्टेशन पूरी तरह विकसित किए जा चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा कि पहले केवल रंगाई-पुताई को ही स्टेशन विकास माना जाता था, लेकिन अब 50 वर्षों की भविष्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें स्थानीय वास्तुकला का समावेशन, दोनों ओर से स्टेशन तक आसान पहुंच, आधुनिक फुटओवर ब्रिज, बड़े पैसेंजर हॉल, पार्किंग क्षेत्रों का विकास तथा स्टेशन एक्सेस को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में छठ और दीपावली के दौरान यात्रियों की भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए नई दिल्ली स्टेशन से शुरू किए गए बड़े होल्डिंग एरिया की व्यवस्था को 50–60 स्टेशनों तक विस्तारित किया गया, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिली। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार अत्यंत गंभीर और व्यवस्थित प्रयासों के साथ देश के रेलवे स्टेशनों के आधुनिक पुनर्निर्माण की दिशा में काम कर रही है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।

बिना ट्रैफिक रोके पहली बार हो रहा है स्टेशन पुनर्विकास : रेल मंत्री

नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़े प्रश्नों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि स्टेशन पुनर्विकास अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें ट्रैफिक रोके बिना बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करना शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह का व्यापक स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्य हाथ में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सपा के सदस्य धर्मेंद्र यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि देश में स्टेशन विकास एक नई तरह की चुनौती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चंडीगढ़ जैसे स्टेशनों पर भारी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया। जबकि कई देशों में स्टेशन पुनर्विकास के दौरान तीन-चार वर्षों तक ट्रैफिक रोक दिया जाता है।

प. बंगाल में 99 आरओबी और अंडरपास राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में लंबित

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 99 रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरपास राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में लंबित हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण से कांग्रेस सदस्य ईशा खान चौधरी के प्रश्न पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सांसद द्वारा उठाए गए एलसी-43 पर आरओबी संबंधी मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की गई है। सांसद के आग्रह पर एक विशेषज्ञ टीम को स्थल निरीक्षण के लिए भेजा गया था और टीम की रिपोर्ट के आधार पर आरओबी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरओबी के एलाइनमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इस आरओबी के पास लगभग 90 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक फ्लाईओवर भी स्थित है, इसलिए दोनों संरचनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए डिजाइन के सिंक्रोनाइजेशन पर काम किया जा रहा है। रेल मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि पश्चिम बंगाल में कुल 99 आरओबी, फ्लाईओवर और अंडरपास विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जिनमें राज्य सरकार का सहयोग न मिलना प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि 41 परियोजनाओं में एलाइनमेंट पर राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। 14 फ्लाईओवरों की अंतिम ड्राइंग राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है। 27 आरओबी और अंडरपास के लिए राज्य सरकार से एनओसी लंबित है। 10 परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सात फ्लाईओवर/अंडरपास कानून-व्यवस्था संबंधी बाधाओं के कारण रुके हुए हैं। मंत्री ने कहा कि सांसद का मुद्दा बिल्कुल उचित है, लेकिन परियोजना की समयसीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि कार्य की प्रगति राज्य सरकार से मिलने वाले अनुमोदनों पर निर्भर करती है।

राजस्थान की धरती के नीचे छिपे खनिज भंडार में देश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता : अग्रवाल

जयपुर। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज राजस्थान विकास की उस गति से आगे बढ़ रहा है कि जयपुर और दिल्ली के बीच अब कोई अंतर शेष नहीं रहा। उन्होंने धरती के नीचे छिपी राजस्थान की अनंत संपदाओं का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जिंक और केयर्न एनर्जी जैसे उद्योगों ने न केवल चांदी, तेल, गैस और खनिज संपदा की अपार क्षमता को उजागर किया है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती के नीचे छिपा खनिज भंडार पूरे देश को ऊर्जा, धातु और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखता है।

अग्रवाल बुधवार को जयपुर के जेईसीसी सभागार में प्रदेश के पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में सिंगल विंडो क्लीयरेंस और सेल्फ-सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं ने उद्योग स्थापित करना बेहद सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यवसाय करना अन्य जगहों की तुलना में आसान और सुविधाजनक है। उन्होंने राजस्थान में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का वादा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और पीले से हरे राजस्थान के निर्माण का सपना साकार होगा।

समारोह को संबोधित करते हुए टाटा पावर के सीईओ एवं एमडी प्रवीर सिन्हा ने कहा कि राजस्थान की धरती में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 800 गीगावाट सौर और 200 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता मौजूद है, जिसे सही दिशा में विकसित किया जाए तो राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा का 'सोना' पैदा कर पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर का राजस्थान से पुराना और बहुत गहरा संबंध रहा है। कंपनी ने राज्य में ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण तीनों ही क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी टाटा पावर राजस्थान के साथ मजबूती से काम करता रहेगा तथा राज्य के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भागीदार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सशक्त वातावरण और बेहतर इकोसिस्टम तेजी से तैयार हो रहा है।

कार्यक्रम में देश-विदेश में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्रवासी राजस्थानियों अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनमचंद राठी, नरसी कुलरिया, सी.एम. मूंदड़ा और प्रदीप राठौड़ को 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान' से सम्मानित किया गया।

सरकार सरकारी स्कूलों में 50 हजार नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में देशभर के सरकारी स्कूलों में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 हजार नई अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा सदस्य तेजवीर सिंह के डिजिटल क्लासरूम, स्किल आधारित शिक्षा और शिक्षकों की क्षमता निर्माण से जुड़े प्रश्न के उत्तर में प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्कूली शिक्षा के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए कई महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की गयी है। आने वाले एक-दो वर्षों में देश के सभी सेकेंडरी (कक्षा 9 से 12) सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड और भारतनेट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, ताकि स्कूलों को वैश्विक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में लगभग दस हजार अटल टिंकरिंग लैब कार्यरत हैं, जिन्हें वृहद आकार देते हुए अगले पांच साल में इनकी संख्या 50 हजार तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की शिक्षा प्रणाली अधिकाधिक तकनीक आधारित होने जा रही है। प्रधान ने बताया कि शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए जिला स्तरीय डीआईईटी संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है तथा शिक्षक शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है, जो क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि देश के प्रत्येक बच्चे तक एड्यूटेक का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में केंद्र सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है। प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश द्वारा स्वीकार की गई एक सर्वसम्मत और दूरदर्शी नीति है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में देख रहा बड़ा और साहसिक सपना : शुभांशु शुक्ला

कोलकाता। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, ने बुधवार को कहा कि भारत अब 'बड़े और साहसिक सपने' देख रहा है और 41 वर्ष बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में कदम रखकर एक नए युग की शुरुआत कर चुका है।

एएक्सियम-4 मिशन के तहत आईएसएस तक पहुंचने वाले शुभांशु शुक्ला 18 दिन के अंतरिक्ष प्रवास के बाद 17 अगस्त, 2025 को अमेरिका से भारत लौटे थे। कोलकाता स्थित इंडियन सेंटर फॉर स्पेस फिजिक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एक अद्भुत जगह है, जहां गहरी शांति और समय के साथ और भी मोहक होता दृश्य देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा समय वहां रहते हैं, उतना ज्यादा आनंद मिलता है... सच कहूं तो मेरा मन वापसी का नहीं था।

शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष में प्राप्त अनुभव प्रशिक्षण से बिल्कुल अलग था और वह भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य बेहद उज्ज्वल है, क्योंकि देश अब 'बहुत बड़े और साहसिक सपनों' को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने अपने आईएसएस मिशन को 'विजन गगनयान' की दिशा में एक 'महत्वपूर्ण सीढ़ी' बताया और कहा कि इस मिशन से जो अनुभव मिला है, वह राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे अब डिजाइन टीमों और विशेषज्ञ समितियों द्वारा आगामी मिशनों को सही दिशा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। शुक्ला ने कहा कि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 'गगनयान', देश का अपना स्पेस स्टेशन 'भारतीय स्टेशन' और चांद पर मानव अभियान शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि चांद पर उतरने का लक्ष्य वर्ष 2040 तक रखा गया है और अगले 10 से 20 वर्षों में यह क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य कठिन जरूर हैं, लेकिन आप जैसे युवाओं के लिए पूरी तरह संभव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के विस्तार से 'रोजगार के विशाल अवसर' पैदा होंगे। राकेश शर्मा के प्रसिद्ध शब्दों को दोहराते हुए शुक्ला ने कहा कि कक्षा से देखने पर आज भी हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। शुक्ला ने कहा कि भारत का युवा वर्ग अत्यंत प्रतिभाशाली है। उन्हें केंद्रित रहना होगा, जिज्ञासु बने रहना होगा और कठोर परिश्रम करना होगा। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने बताया कि राकेश शर्मा के युग की तुलना में आज भारत ने एक संपूर्ण अंतरिक्ष यात्री पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है। उन्होंने कहा कि गगनयान और आने वाले मिशनों के जरिए भारत के बच्चे अब केवल अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं देखेंगे, बल्कि उसे यहीं देश में पूरा भी कर सकेंगे।

शुक्ला ने कहा कि जब कोई एक व्यक्ति अंतरिक्ष जाता है, तो लाखों सपनों को उड़ान मिलती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का निरंतर जारी रहना बेहद आवश्यक है। अब आसमान ही सीमा नहीं रहा। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि वे ऐसी प्रणालियां विकसित करें जो 20-30 वर्षों तक टिकाऊ हों और भविष्य की तकनीकों के साथ सामंजस्य बैठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे और मिशनों में भाग लेने के इच्छुक हैं और एक 'स्पेस वॉक' करने का सपना देखते हैं, जिसके लिए उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

चुनावी हार की खीज उतारने को चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही कांग्रेस : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। बिहार के पटना साहिब से लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी हार की खीज उतारने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। उन्होंने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने का पूरा अधिकार है।

रविशंकर ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर लगातार दूसरे दिन बुधवार को जारी चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल के लोकसभा में दिए वक्तव्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनके मामले में प्रतिवादी होने के कारण उन्हें अपनी बात सदन में रखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि वेणुगोपाल के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। उनके वक्तव्य के बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उनकी आपत्ति पर विचार किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने कहा कि जब कांग्रेस और अन्य दल चुनावों में जीत दर्ज करें तब सब ठीक है और जब हार जायें तो चुनाव आयोग, ईवीएम पर दोष लगाया जाता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करना अस्थाई प्रक्रिया थी जिसे सरकार ने कानून लाकर बदला है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में किस प्रकार नियुक्ति होती थी।

पुणे पोर्श मामले में लापरवाही के चलते दो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया

पुणे। महाराष्ट्र के इस शहर में पिछले साल पोर्श कार दुर्घटना की जांच में कथित लापरवाही के लिए निलंबित किए गए दो पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कल्याणी नगर इलाके में 19 मई 2024 के तड़के कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा नशे की हालत में चलाई जा रही पोर्श कार ने मोटरसाइकिल पर सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि येरवडा थाने में तैनात निरीक्षक राहुल जगदाले और सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) विश्वनाथ तोडकरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वे दुर्घटना के मामले में देर से रिपोर्ट करने और कर्तव्य में लापरवाही के लिए पहले से ही निलंबित थे। उन्हें बर्खास्त करने का एक प्रस्ताव मार्च 2025 में गृह विभाग को भेजा गया था। अधिकारी ने कहा कि एक आंतरिक जांच में मामला दर्ज करते समय खामियां और रक्त के नमूने एकत्र करने में देरी का पता चला था।

कोलकाता हवाई अड्डे पर सभी सेवाएं सामान्य यात्रियों को मिल रही है निर्बाध सुविधा

कोलकाता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी सेवाएं पूर्णतः सामान्य हैं। विमानों का आगमन और प्रस्थान सुचारू रूप से जारी है तथा यात्री सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाऐं बिना किसी अवरोध के संचालित हो रही हैं।

एएआई कोलकाता हवाई अड्डे के बुधवार को जारी बयान के अनुसार, यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विमान सेवाओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भूमिसेवा एजेंसियों और अन्य सभी परिचालन इकाइयों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांव क्षेत्र, आव्रजन विभाग और सामान बैल्ट जैसे प्रमुख यात्री स्पर्श-बिंदुओं पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को समय पर सहायता मिल सके। हवाई अड्डे पर सहायता केंद्र और सूचना काउंटर चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। साथ ही यात्रियों को आवश्यक जानकारी नियमित उद्घोषणाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे जारी परामर्शों का पालन करें तथा उड़ान संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए अपनी संबंधित विमान सेवा से संपर्क करें।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

नशे से बचकर ही खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे युवा: मुख्यमंत्री

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां सामने हैं। एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों ही नशे से बचना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे, उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित मुख्य महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि नशा माफिया तेजी के साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को भी इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर नहीं दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन पर युवाओं का अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करना होगा। उन्होंने युवाओं को समझाया, हालांकि एकाएक यह कर पाना कठिन होगा, इसलिए धीरे-धीरे कम करिए। आवश्यक हो तभी आधा या एक घंटा तक ही आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए। समय तय करिए कि मुझे जब आवश्यक बात करनी है तभी बात करूंगा, अनावश्यक नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आपकी आंख की साइट को प्रभावित करेगा। मस्तिष्क को कुंद कर देगा, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को भी यह पूरी तरह कमजोर कर देगा। इसलिए स्मार्टफोन से जितना बच सकते हैं, बचने का प्रयास करना चाहिए।

समय और तकनीक के साथ चलते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की सीख देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक्स के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हममें से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उस मानसिकता से भी उबरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। यह तथ्य सही नहीं है बल्कि तकनीक आएगी रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हमें अपने आप को उसके अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है और धैर्य बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हार तभी होती है जब हम हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की बजाय, अंधकार को धिक्कारने की बजाय, यदि हम 'आओ मिलकर दीया जलाएं' का काम करने लग जाएं, हर व्यक्ति मिलकर एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क का महत्व समझाते हुए कहा कि यह केवल एक गेम में नहीं बल्कि पूरी जनरेशन में उपयोगी होता है। हमें अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, टीम वर्क से जोड़ना पड़ेगा।

सीएम ने कहा कि यह भी याद रखना होगा, शॉर्ट कट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति और संस्था को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। युवाओं और अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा।

संस्थापक सप्ताह के मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में स्वागत संबोधन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह, आभार ज्ञापन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष राजेश मोहन सरकार और संचालन डॉ. श्रीभगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. के. रामचंद्र रेड्डी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की कुलपति प्रो. कविता शाह, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर की कुलपति प्रो. शोभा गौड़, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत मिथिलेशनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, भारत सरकार के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉ. जीएन सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. वीके सिंह, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी व सदस्य, परिषद से जुड़ी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों व विद्यार्थियों की सहभागिता रही।

संस्थाओं और मेधावियों को किया गया पुरस्कृत

संस्थापक सप्ताह के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में से उत्कृष्ट संस्था, उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट कर्मचारी, उत्कृष्ट परिचारक और स्नातकोत्तर, स्नातक एवं हाईस्कूल-इंटर के उत्कृष्ट विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंच से करीब डेढ़ सौ पुरस्कार वितरित किए गए। करीब सात सौ पुरस्कार, संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

प्रो यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ सहित दो पुस्तकों का हुआ विमोचन

संस्थापक समारोह के मुख्य महोत्सव में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ और एमपीपीजी कॉलेज जंगल धूसड़ की पुस्तक 'जीवन मूल्य प्रमाण पत्र संग्रह पाठ्यक्रम' का विमोचन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने प्रो. यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ की प्रकाशन संस्था प्लाक्षा के प्रबंध निदेशक सौरभ सिंह को स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया।

उप्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से अनुपूरक बजट व कई विधेयक पेश करने की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 'बाई सर्कुलेशन' के माध्यम से इस सत्र की तिथियों को मंजूरी दी और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद इन तिथियों की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की संक्षिप्त अवधि को देखते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसमें प्रमुख विभागों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए धनराशि की मांग की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी रखने वाली है। इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव भी शामिल बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने पहले ही शीतकालीन सत्र के कम समय होने पर सवाल उठाए हैं। इस बार भी सत्र की सीमित अवधि और विपक्ष की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सदन में सरगर्मी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सदन में सरकार संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी पेश कर सकती है।

फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही विधानसभा सचिवालय सत्र की विस्तृत कार्यसूची जारी करेगा। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार विधानमंडल के सत्र को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब राज्यपाल की अधिसूचना के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर का समय बढ़ाने लिए चुनाव आयोग को लिखा पत्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का समय 14 दिन बढ़ाने की मांग की है। अब इस पर निर्वाचन आयोग जल्द ही कोई फैसला ले सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा 14 दिन और बढ़ा दी जाएगी। समय मांगने की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आयोग ने एसआईआर के लिए दूसरी बार समय बढ़ाकर 11 दिसंबर अंतिम तिथि तय की थी। उधर, एसआइआर के बीच उत्तर प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने के उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14 प्रतिशत (12.40 करोड़) डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें 2.91 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले हैं। यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को दी जाएगी। इसके साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी लगाई जाएगी। इस सूची में जो लोग मिल जाएंगे, उनके गणना प्रपत्र भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इन 2.91 करोड़ में 46 लाख मृत, 1.27 करोड़ स्थानांतरित, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 84.73 लाख अनुपस्थित व अन्य 9.57 लाख मतदाता हैं।

गाजियाबाद। पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति इंदिरापुरम द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का समिति के अध्यक्ष सागर रावत ने मेला परिसर में स्थापित मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया।

धान खरीद में धांधली के आरोप में दो लेखपाल निलंबित, बिचौलियों पर मुकदमा

शाहजहांपुर। जिले में धान खरीद में धांधली करने के आरोप में दो लेखपालों को निलंबित कर फर्जी सत्यापन कराने वाले बिचौलियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि तिलहर तथा पुवाया में दो लेखपालों ने बिना जांच किए मांग पत्र के आधार पर किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल का फर्जी सत्यापन कर दिया जबकि तिलहर में जिसके नाम का सत्यापन किया गया उसके नाम पर जमीन ही नहीं है। वहीं, पुवाया में जिस जमीन में गन्ना बोया गया था वहां धान की फसल दिखाकर सत्यापन किया गया। बाद में बाजार से धान खरीद करके उसे सरकारी क्रय केंद्र पर भेजा गया। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में शिकायत के बाद जांच कराई गई और पुवायां के लेखपाल आशीष कुमार तथा तिलहर के अंशु बाजपेई को निलंबित कर दिया गया है वहीं फर्जी सत्यापन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने और उसकी पुष्टि होने के बाद अब अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वह धान क्रय केंद्रों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण करें तथा शाम को उनके व्हाट्सएप पर केंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए नियमित रिपोर्ट भेजें।

सपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जनता नहीं देगी इन्हें मौका : ब्रजेश पाठक

फिरोजाबाद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को सपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता इनके जंगलराज को नहीं भूली है, इसलिए इन्हें कभी मौका नहीं देगी। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिससे घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद स्थित भाजपा कार्यालय पर एसआईआर की समीक्षा बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। सपा और अन्य विपक्षी दल घुसपैठियों के वोटों की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी कारण इनके पेट में दर्द हो रहा है। जबकि भाजपा सुचितापूर्ण तरीके से चुनाव लड़ना चाहती। यूपी में भाजपा 2017 से शासन में है, इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और सही मतदाताओं के फॉर्म भरवाने का अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सभी अवैध, मृतक और नाबालिग मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। 16 दिसंबर के बाद नई सूची का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही शादीशुदा बहुओं तथा ट्रांसफर होकर आए लोगों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान प्रक्रिया आजादी के बाद कई बार की गई है और इसमें कोई डरने की बात नहीं। भाजपा पारदर्शिता और संविधान की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गलत राजनीतिक क्रियाकलाप करने का आरोप भी लगाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बिहार की जनता आरजेडी के जंगलराज को नहीं भूली है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता भी सपा के जंगलराज, गुंडाराज को भूलने वाली नहीं है।

साइकिल यात्रा निकालकर ग्राम सचिवों ने किया विरोध-प्रदर्शन

मीरजापुर। जमालपुर ब्लॉक मुख्यालय पर बुधवार को ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों ने साइकिल यात्रा निकालकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से साइकिल भत्ता बढ़ाने और अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को तत्काल खत्म करने की मांग की। ग्राम सचिवों का कहना है कि वर्तमान में मात्र 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जा रहा है, जो उनके दैनिक कार्यों और दूर-दराज के गांवों में आने-जाने के खर्च को देखते हुए बेहद कम है। उन्होंने कहा कि यह राशि बढ़ाना समय की जरूरत है। विरोध-प्रदर्शन के तहत ग्राम सचिवों ने पूरे जमालपुर बाजार में साइकिल रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। ब्लॉक अध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि अगर शासन-प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेता है, तो 15 दिसंबर को सभी ग्राम सचिव डोंगल जमा कर कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। प्रदर्शन में कमलेश पाल, गोविंद यादव, राहुल सिंह, योगेश सिंह, चंदन गुप्ता, संतोष सिंह, इंद्रावती देवी, मुकेश गौतम और राजा प्रसाद सहित कई ग्राम सचिव मौजूद रहे।

लापता हुए बीटेक के छात्र का शव पोखर से बरामद

झांसी। झांसी जिले के गुरसराय इलाके में लापता हुए बीटेक के एक छात्र का शव संदिग्ध हालत में सड़क के किनारे एक पोखर से बरामद किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गुरसराय थाना क्षेत्र स्थित सिंगार गांव के निवासी अरविंद पटेल का 19 वर्षीय बेटा मृदुल बीटेक का छात्र था जो छुट्टी पर घर आया था। चार दिसंबर की शाम वह अपने स्कूटर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि तलाश किए जाने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चलने पर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को बमौरी मार्ग के किनारे स्थित एक गहरे पोखर में उसका शव मिला। उसकी स्कूटी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

भूखंड आवंटन में जालसाजी के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार

लखनऊ। लखनऊ पुलिस ने बुधवार को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 1999 में देवरिया जिले में एक भूखंड के आवंटन से जुड़े जालसाजी के कथित मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ठाकुर ने 1999 में देवरिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग कर जाली दस्तावेज और गलत पहचान का इस्तेमाल करके जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक औद्योगिक भूखंड का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर करवाया। बाद में उन्होंने भूखंड को अपने फायदे के लिए बेच दिया।

पुलिस उपायुक्त (लखनऊ पश्चिमी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि इस बारे में लखनऊ के ताल कटोरा क्षेत्र के राजाजीपुरम के रहने वाले संजय शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आवंटन पाने के लिए गलत नाम, पते और जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया जबकि ठाकुर ने कथित तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके सुरक्षा और मदद दी। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर ताल कटोरा थाने में गत 12 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के मुताबिक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक विशेष टीम (एसआईटी) बनाई थी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि जांच के दौरान देवरिया जिले से सबूत इकट्ठा किए गए, बिहार में कथित गलत नामों और पतों की पड़ताल की गयी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सुबूतों के आधार पर ठाकुर को बुधवार तड़के करीब तीन बजकर 45 मिनट पर सीतापुर जिले की महोली सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया और अब देवरिया की अदालत में पेश किया जाएगा।

लापरवाही पर 2 एएनएम की सेवा समाप्त, सचिव निलंबित

सीतापुर। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) पर लापरवाही उजागर होने के बाद जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बुधवार को विकास खंड सिधौली के ग्राम सचिवालय बाड़ी और पंचायत भवन जटहा के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिधौली में भारी अव्यवस्था मिलने और अनुपस्थित एएनएम रंजू देवी की सेवा तत्काल समाप्त करने का निर्देश डीएम ने दिए। वहीं आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्साधिकारी को डीएम ने लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। जटहा पंचायत भवन पहुंचते ही डीएम का गुस्सा और भड़क गया। वीएचएसएनडी दिवस पर देरी से पहुंचने पर एएनएम सोनी शुक्ला की सेवा भी समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए। पंचायत भवन में अव्यवस्थाएं मिलने पर डीएम ने सचिव आरती यादव को निलंबित करने का आदेश दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति और खराब कार्यशैली पर जिलाधिकारी ने कड़ा असंतोष जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। वहीं ड्यू रजिस्टर और अन्य अभिलेख अद्यतन न मिलने पर बीपीएम राजू मौर्य पर नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के चौथे वर्षगांठ पर होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान,फूलों से सज रहा दरबार

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी (काशी)में स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के चौथे वर्षगांठ की तैयारियां शुरू हो गई है। श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् (काशी विश्वनाथ धाम) में विविध धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूरे धाम की फूलों से भव्य सजावट होगी। चौथी वर्षगांठ पर धाम में 13 और 14 दिसंबर को भव्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार पूरे धाम परिसर को 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विविध प्रकार के फूलों से आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। आम श्रद्धालु भी इन चार दिनों में धाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष दर्शन कर सकेंगे। उत्सव में 14 दिसंबर को धाम में वृहद् शास्त्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें जाने-माने कलाकार मंदिर चौक के मंच पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। बताते चले 13 दिसंबर को धाम के उद्घाटन (2021) के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि मार्गशीर्ष माह की दशमी, इस वर्ष 14 दिसंबर को पड़ रही है। दोनों ही दिनों में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं, बाबा के इस खास उत्सव में शिव बारात समिति और संस्कृति विभाग की पहल पर तीन किमी लम्बी भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

मंदिर न्यास के अनुसार धाम के लोकार्पण के बाद चार सालों में अब तक कुल 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की अवधि में मात्र डेढ़ माह में 2 करोड़ 87 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इतनी बड़ी संख्या में धाम में श्रद्धालुओं का आना और निर्बाध दर्शन पूजन बड़ी उपलब्धि रही। धाम में बीते चार वर्षों में कई नवाचार किए गए, इनमें सांसद संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन भी है। संस्कृत विद्यालयों के बच्चों को भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकें प्रदान करना,मथुरा, रामेश्वरम, अयोध्या सहित देश के बड़े मंदिरों से गहरा सांस्कृतिक और पारस्परिक संबंध स्थापित करना,सनातन संस्कृति की एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास, श्रद्धालुओं विशेषकर वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों के लिए उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। काशीवासियों के लिए अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गई है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में शुभमन गिल पर रहेगी नजर

मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़)। अभी तक सबसे छोटे प्रारूप में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपने घरेलू मैदान पर फॉर्म में वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पांच मैचों की इस श्रृंखला के पहले दो मैचों के बीच केवल एक दिन का अंतराल है और ऐसे में गिल को सीधे मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारत ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से करारी शिकस्त दी लेकिन सितंबर में एशिया कप में टी20 टीम में वापसी करने वाले गिल का औसत प्रदर्शन अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन टी20 में वह अपनी इस सफलता को नहीं दोहरा पाए हैं जिससे उन पर दबाव बनना स्वाभाविक है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी टीम प्रबंधन ने गिल की टी20 सलामी बल्लेबाज के रूप में क्षमता पर अधिक भरोसा दिखाया। इसके बाद संजू की टीम में जगह अनिश्चित हो गई। टेस्ट और वनडे कप्तान गिल आसानी से वह भूमिका निभा सकते हैं जो विराट कोहली ने पिछले साल टी20 विश्व कप तक भारत के लिए निभाई थी। भारतीय टीम में आठवें नंबर तक बल्लेबाजी के विकल्प मौजूद हैं और उसने अब अपने निडर दृष्टिकोण को और मजबूत कर लिया है, जिससे एक सूत्रधार के लिए बहुत कम जगह बची है।

गिल निश्चित रूप से पावरप्ले में अभिषेक शर्मा की तरह आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें यह पता लगाना होगा कि वह अपनी भूमिका कैसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। गिल के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले विश्व कप से पहले चिंता का विषय बना हुआ है। उनका विश्व कप से पहले फॉर्म में लौटना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न्यू चंडीगढ़ के ठंडे वातावरण में भारत का अपने विजयी संयोजन में कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है। चोट से उबरकर राष्ट्रीय टीम में वापसी करते हुए हार्दिक पंड्या ने अदद ऑलराउंडर के रूप में अपनी स्थिति को फिर से साबित कर दिया। कटक में पहले मैच में उनकी 28 गेंदों में खेली गई 59 रन की पारी ने मुश्किल विकेट पर बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। वह अपने इस प्रदर्शन को यहां भी जारी रखने के लिए उत्सुक होंगे। पहले मैच में खेलने वाली टीम से यह भी संकेत मिला कि दो प्रमुख गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव एक साथ अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं हो सकते हैं क्योंकि टीम प्रबंधन आठवें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज को रखने के पक्ष में है। पहले मैच में अर्शदीप को मौका मिला और इस प्रारूप में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले इस तेज गेंदबाज ने जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर टीम को शुरुआती विकेट दिलाए।

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी चिंता का विषय होगा क्योंकि उसकी टीम 176 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 74 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्क्रम ने भी स्वीकार किया कि उनके बल्लेबाज परिस्थितियों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। मार्क्रम ने पहले मैच के बाद कहा, ''आजकल टी20 क्रिकेट में चीजों को समझने का ज्यादा समय नहीं मिलता।

लेकिन सबसे बड़ा कारण स्पष्ट रूप से साझेदारी न बना पाना, विकेट गिरने के बाद संभल न पाना और लय न बना पाना था। हमें इस पर गौर करना होगा।'' सितंबर में दो महिला वनडे मैचों की मेजबानी करने के बाद इस मैदान पर पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। मैच के दौरान युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर बने स्टैंड का भी अनावरण किया जाएगा।

इस प्रकार हैं दोनों टीम

- **भारत:** सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, संजू सैमसन।
- **दक्षिण अफ्रीका:** एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन।

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।

कोहली वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे, रोहित शर्मा शीर्ष पर बरकरार

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज बनने की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की ओर से बुधवार को जारी ताजा मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में कोहली ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि रोहित शर्मा नंबर-1 की कुर्सी पर बने हुए हैं।

कोहली ने पाकिस्तान के बाबर आजम के हाथों अप्रैल 2021 में वनडे बल्लेबाजों की नंबर-1 रैंकिंग गंवाई थी, लेकिन अब वह एक बार फिर शीर्ष स्थान के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली को रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला। 37 वर्षीय कोहली ने सीरीज में कुल 302 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। सीरीज के आखिरी मुकाबले में विशाखापत्तनम में खेली गई नाबाद 65 रन की पारी के दम पर कोहली अब रोहित शर्मा से सिर्फ आठ रेटिंग अंकों पीछे हैं। वहीं रोहित शर्मा ने सीरीज में 146 रन बनाकर अपनी नंबर-1 पोजिशन बरकरार रखी। रोहित के 781 रेटिंग अंक हैं, जबकि कोहली के 773 रेटिंग अंक हैं।

भारतीय टीम अब 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जहां कोहली और रोहित के बीच नंबर-1 स्थान की रेस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों को भी ताजा रैंकिंग में फायदा हुआ है। विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल दो स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जो इस सूची में सबसे बड़ा फायदा है।

जूनियर महिला विश्व कप हॉकी: निधि के शानदार प्रदर्शन से भारत ने उरुग्वे को हराया

सैंटियागो (चिली)। गोलकीपर निधि के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पेनल्टी शूटआउट में उरुग्वे को 3-1 से हराकर जूनियर महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में में नौवें स्थान पर रहने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। नौवें से 12वें स्थान के लिए खेले गए इस क्लासिफिकेशन मैच में दोनों टीम निर्धारित समय तक 1-1 से बराबरी पर थी।

भारत की तरफ से मनीषा ने 19वें मिनट जबकि उरुग्वे के लिए जस्टिना अरेगुई ने 60वें मिनट में गोल किया। पेनल्टी शूटआउट में भारत की तरफ से पूर्णिमा यादव, इशिका और कनिका सिवाच ने गोल किए, जबकि गोलकीपर निधि ने उरुग्वे के तीन गोल का बचाव करके अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। पहले क्वार्टर में भारत का दबदबा रहा और उसने शुरुआत में ही कई मौके बनाए। हालांकि उरुग्वे को पांचवें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाया। भारत ने 18वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन साक्षी राणा का शॉट विपक्षी गोलकीपर ने रोक दिया। इसके कुछ क्षण बाद ही मनीषा ने हालांकि भारत को बढ़त दिला दी। इसके बाद अगले दो क्वार्टर में दोनों टीम ने गोल करने के लिए कई प्रयास किए नहीं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंतिम क्वार्टर में उरुग्वे ने अधिक खुलकर खेलना शुरू किया। जब मैच समाप्त होने में दो मिनट का समय बचा था तब उरुग्वे ने गोलकीपर की जगह एक फील्ड खिलाड़ी को मैदान में उतारा और उसकी यह रणनीति कारगर साबित हुई। अब खेल समाप्त होने में केवल दो सेकंड का समय बचा था कि तभी उरुग्वे को पेनल्टी मिली। जस्टिना अरेगुई ने इसे गोल में बदलकर मैच को शूटआउट में पहुंचा दिया, जिसमें निधि के शानदार खेल से भारत जीत हासिल करने में सफल रहा। भारत का अगला मुकाबला नौवें स्थान के लिए गुरुवार को स्पेन से होगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में की टी20 दौरे की तैयारियों की समीक्षा

लाहौर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी टीम के जनवरी में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए लाहौर में है। प्रतिनिधिमंडल में एक स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकार और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक अधिकारी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया अगले साल की शुरुआत में पाकिस्तान का दौरा करेगा और दो चरणों में सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगा। पहले चरण में जनवरी में तीन मैचों की टी20 श्रृंखला होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक इस श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगता है कि तीनों मैच लाहौर में ही खेले जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और उस होटल का दौरा शामिल है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ठहरेगी। वे पीसीबी अधिकारियों तथा सरकारी और सुरक्षा प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगले साल मार्च में तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए फिर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि वनडे श्रृंखला को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है और इसका आयोजन 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप से पहले किसी समय हो सकता है।

चोटें आपकी मानसिक मजबूती की परीक्षा लेते हैं, दमदार वापसी चाहता था: हार्दिक

कटक। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का मानना है कि चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने के बाद वह सकारात्मक मानसिकता से ही 'दमदार और बेहतर वापसी' करने में सफल रहे। एशिया कप के दौरान चोटिल होने वाले इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने भारतीय टीम में शानदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 28 गेंद पर नाबाद 59 रन की तूफानी पारी खेली और फिर 16 रन देकर एक विकेट लिया। भारत ने इस मैच में 101 रन से बड़ी जीत हासिल की। हार्दिक ने एक वीडियो में कहा कि मेरी सोच यह थी कि मैं पहले की तुलना में अधिक दमदार और बेहतर वापसी करूं। चोटें मानसिक रूप से आपकी परीक्षा लेती हैं और साथ ही कई तरह के संदेह भी पैदा करती हैं। इससे उबरने में अपने करीबी लोगों का भी बड़ा योगदान होता है।

हार्दिक पंड्या ने कहा कि मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा जिससे मुझे अधिक आत्मविश्वास मिला तथा खुद पर भरोसा करने और अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास करने में मदद मिली है। मुझे एक खिलाड़ी के रूप में खुद पर पूरा भरोसा है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे आप पर कैसे विश्वास करेंगे।'' टी20 विश्व कप में भारतीय अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी हार्दिक ने कहा कि वह ऐसे इंसान हैं जो आत्मविश्वास अपने भीतर से प्राप्त करता है और लोग क्या सोच रहे हैं इसकी ज्यादा परवाह नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं जीवन में बेहद ईमानदार और यथार्थवादी इंसान रहा हूं जिससे मुझे बहुत मदद मिली है। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं हमेशा इस पर ध्यान देता हूं कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूं।

हार्दिक ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हार्दिक पंड्या सिर्फ खेल खेलना चाहता है, मैदान पर हर पल का आनंद लेना चाहता है। अब बड़ा और बेहतर बनना ही मेरे जीवन का ध्येय है। पंड्या का कहना है कि दर्शकों के समर्थन से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है, जो उन्हें उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि आपको एक रॉकस्टार होना चाहिए। आप आते हैं, 10 मिनट तक परफॉर्म करते हैं और भीड़ पागल हो जाती है, मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मैंने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया और उनसे सबक लिया। इसलिए जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं तो मुझे लगता है कि दर्शक बस मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए ही इंतजार कर रहे हैं।

रुपया नौ पैसे टूटकर 89.96 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुझान और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच रुपया बुधवार को नौ पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.96 (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि निवेशक निर्णायक रुख अपनाने से पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निवेशक अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता से मिलने वाले संकेतों का भी इंतजार कर रहे हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.00 प्रति डॉलर पर खुला। फिर कारोबार के दौरान लुढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.10 पर आ गया। कारोबार के अंत में 89.96 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव के मुकाबले नौ पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.87 पर बंद हुआ था।

ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता अंतिम चरण में: पीयूष गोयल

जयपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में है और दोनों के जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने संकेत दिया कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली के साथ भी व्यापार समझौते के लिए बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयलने कहा कि ओमान के साथ समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले शुक्रवार को नयी दिल्ली आ रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस बीच, वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि गहन वार्ता के तीन दौर (नवंबर 2023-मार्च 2024) के बाद दोनों पक्ष सीईपीए (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) के सभी घटकों पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिसमें पाठ्य एवं बाजार पहुंच प्रस्ताव शामिल हैं। इसमें कहा गया कि मार्च 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आगे की बातचीत की आवश्यकता पड़ी। चौथे दौर (सितंबर 2024) और पांचवें दौर (13-14 जनवरी 2025) में संशोधित प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कहा गया कि प्रासंगिक प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, हस्ताक्षर व पुष्टि के लिए मंत्रिमंडल 'नोट' का मसौदा संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया। दोनों पक्ष अब आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। इजराइल के साथ व्यापार समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ हाल ही में बैठक की थी और दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के लिए अपने मुख्य वार्ताकारों को नियुक्त कर दिया है।

तेल अवीव में दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा कि हमें उम्मीद है कि इजराइल के साथ पहले चरण की शुरुआत होगी। मंत्री पीयूष गोयल 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' में हिस्सा लेने यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत व्यापार एवं वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने को इच्छुक हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और इजराइल 2010 से एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें 280 शुल्क श्रेणियों या उत्पाद श्रेणियों को शामिल करने वाले 10 दौर पूरे हो चुके हैं।

इसके अलावा, इसमें कहा गया कि भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर तीन जुलाई 2025 को माले में हस्ताक्षर किए गए थे। टीओआर आगामी एफटीए वार्ताओं के लिए ढांचा एवं दायरा निर्धारित करता है। समझौते पर वार्ता शुरू हो चुकी है। भारत और कतर भी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने हेतु एक टीओआर को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी तरह की प्रक्रिया भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच भी जारी है।

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 275 अंक टूटा

मुंबई। टिकाऊ उपभोक्ता, निजी बैंकों और आईटी शेयरों में बिकवाली के बीच स्थानीय शेयर बाजार के मानक सूचकांक बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 275 अंक गिर गया जबकि निफ्टी में 82 अंक की गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 275.01 अंक यानी 0.32 प्रतिशत गिरकर 84,391.27 अंक पर बंद हुआ। यह 11 नवंबर के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,020.34 के ऊपरी और 84,313.62 के निचले स्तर को छुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी अंतिम घंटे की बिकवाली के दबाव में 81.65 अंक यानी 0.32 प्रतिशत गिरकर 25,758 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के आखिरी घंटों में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, निजी बैंक और आईटी शेयरों में हुई बिकवाली ने शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया और सेंसेक्स एवं निफ्टी एक महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स के शेयरों में इटर्नल, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआई सीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर गिरावट में रहे।

टाटा स्टील, सन फार्मास्यूटिकल्स, आईटीसी, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावरग्रिड और एशियन पेंट्स के शेयरों में बढ़त रही। जियोजीत इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि भारतीय बाजारों ने वैश्विक सतर्कता का अनुसरण किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, रुपये की कमजोरी और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में अनिश्चितता से धारणा प्रभावित हुई।

श्रम मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश में रोजगार अवसर बढ़ाने, कृत्रिम मेधा (एआई) कौशल के विकास एवं कार्यबल की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह सहयोग रोजगार संबंधों को विस्तारित करने, एआई-आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देने और भारत के कार्यबल को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला की उपस्थिति में इस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने व्यापक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से 15,000 से अधिक नियोक्ताओं एवं भागीदारों को मंत्रालय के 'नेशनल करियर सर्विसेज' (एनसीएस) मंच पर आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि यह साझेदारी भारत के अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, डिजिटल रूप से कुशल एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल खड़ा करने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में 2015 में 19 प्रतिशत आबादी थी जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया। इससे 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है। ई-श्रम और एनसीएस जैसे मंचों में एआई को अपनाकर हम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं और मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं।

नडेला ने भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भारत के उल्लेखनीय विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब 64.3 प्रतिशत आबादी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे 94 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ई-श्रम पहल की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने लाखों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का काम किया है। साथ ही वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर श्रमिक-केंद्रित नीतियां बनाने की भारत की क्षमता को मजबूत किया है।

सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक फर्मों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक फर्मों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत मान्यताप्राप्त फर्म आयकर छूट जैसे प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाती हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आज की तारीख तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कुल 2,01,335 स्टार्टअप को मान्यता दी है। इन स्टार्टअप ने देश भर में 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। बयान के मुताबिक, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में जून 2025 तक 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश हासिल किया जा चुका है। पीएलआई योजनाओं के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात भी हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, औषधि, दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डिजिटल वाणिज्य के लिए खुले नेटवर्क की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सरकारी ई-कॉमर्स मंच ओएनडीसी ने अक्टूबर 2025 तक 32.6 करोड़ से अधिक ऑर्डर पूरे किए हैं। कारोबारी सुगमता पर मंत्रालय ने कहा कि नवंबर, 2025 तक 47,000 से अधिक अनुपालन नियमों को हटाया जा चुका है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 18 अगस्त 2025 को जन-विश्वास विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया।

अदाणी समूह 2031 तक भारत में 12 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा: गौतम अदाणी

धनबाद (झारखंड)। बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में फैले अदाणी समूह की अगले छह वर्षों में भारत में 12 लाख करोड़ रुपये तक निवेश करने की योजना है। समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने यह जानकारी दी। अदाणी ने कहा कि बुनियादी ढांचे, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और बंदरगाहों समेत अन्य क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया जाएगा। अडाणी ने कहा कि निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हम अगले छह साल में भारत में 10 से 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

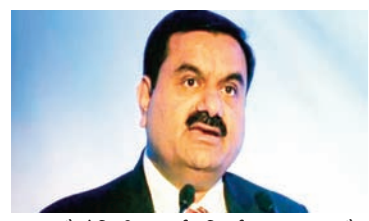

उद्योगपति ने कहा कि कोरपोरेट भारत और उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ जुड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने भारत की नई स्वतंत्रता बताया है। अदाणी ने कहा कि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए संघर्ष जारी है... प्रधानमंत्री ने भी इसका आह्वान किया है... यह एक नई आजादी है। हर उद्योगपति और हर समूह इसी पर काम कर रहा है। वह आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए यहां आये थे। उन्होंने कहा, प्रस्तावित निवेश में बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा परिवर्तन, बंदरगाह और अन्य चीजें शामिल होंगी। अदाणी ने कहा कि हमने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक बनने के लिए निवेश किया है... हम ऐसे विस्तार की तैयारी कर रहे हैं जो अगले दशक के लिए भारत की आकांक्षाओं से मेल खाता हो।

अदाणी समूह गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है, जो 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ष 2030 तक पूरी क्षमता पर इस पार्क से 30 गीगावॉट हरित ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो प्रति वर्ष छह करोड़ से अधिक घरों को बिजली देने के बराबर होगी।

मुझे लगता है कि मैंने बस अभी-अभी अपना सफर शुरू किया है : कार्तिक आर्यन

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन का कहना है कि उन्हें लगता है कि कि उन्होंने बस अभी-अभी अपना सफर शुरू किया है। कार्तिक आर्यन को फिल्म इंडस्ट्री में आये हुये एक दशक से अधिक का समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। हालांकि कार्तिक आर्यन को लगता है कि उन्होंने बस अभी-अभी अपना सफर शुरू किया है। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में सउदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने बॉलीवुड सफर को एक ऐसी कहानी बताई है, जो अभी पूरी तरह लिखी ही नहीं गई है। सफलता के कई पड़ावों को पार करने के बावजूद, कार्तिक अपने करियर को एक निरंतर विकसित होती स्क्रिप्ट मानते हैं, जहाँ हर उपलब्धि नई महत्वाकांक्षाओं और नए अवसरों का रास्ता खोलती है, फिर चाहे वह भारत में हों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कार्तिक ने कहा, "मुझे लगता है कि मैंने बस अभी-अभी अपना सफर शुरू किया है। हालांकि कहानी अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाएगी। आप इसे कहानी का शुरुआती दौर भी कह सकते हैं, जिसे पूरी होने में काफी वक्त लगेगा।" कार्तिक ने अपने लगातार आगे बढ़ने के जज़्बे पर भी बात करते हुए कहा, "मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी मैं यहाँ हूँ, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो मुझे उससे भी आगे जाना होगा। फिर वहाँ से और आगे। यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, जो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं संतुष्ट हो जाऊँ, तो आगे के लिए कभी कोशिश नहीं करूंगा। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे वैश्विक मंच पर खड़े होकर कार्तिक के कहे यह शब्द न सिर्फ उनके अंतरराष्ट्रीय आकर्षण को दिखाते हैं, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर करते हैं।

'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' रिलीज

न्यू ईयर पार्टी सीजन को और जोश से भरने आ गया है 'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है। ज़ी स्टूडियोज और बीलाइव प्रोडक्शन्स ने लंबे इंतज़ार और जबरदस्त बज़ के बाद फिल्म का टीज़र जारी किया, जिसमें इसकी मजेदार, कॉस्मिक और पूरी तरह हटकर दुनिया की झलक दिखाई गई है। टीज़र के तुरंत बाद रिलीज हुआ गाना 'मदिरा', जिसे देखकर साफ है कि यह इस साल की हर पार्टी का नया एंथम बनने जा रहा है। गाने में शालिनी पांडे अपनी बोल्ड, ग्लैमरस और पहले कभी न देखी गई स्टाइलिश पर्सनैलिटी के साथ सबकी निगाहें खींच लेती हैं। उनके एनर्जेटिक और स्मूद डांस मूव्स गाने की वाइब को और भी हाई-ऑक्टेन बना देते हैं। वहीं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा अपनी मजेदार केमिस्ट्री, शार्प कोरियोग्राफी और बिंदास अंदाज़ से इस पार्टी नंबर को पूरी तरह धमाल बना देते हैं। 'मदिरा' को विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने कंपोज़ किया है। इसे सिमर कौर, अभिनव शेखर और विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि इसके बोल भी अभिनव शेखर ने लिखे हैं। इस ट्रैक के बारे में विक्रम मॉन्ट्रोज़ का कहना है कि उन्होंने ऐसा गाना तैयार किया है जो 'राहु केतु' की मस्ती, पागलपंती और बिंदास ऊर्जा को एकदम सही तरीके से कैप्चर करता है, ₹बस मूड में आओ और पल को जी लो। विपुल गर्ग के निर्देशन में बनी 'राहु केतु' को ज़ी स्टूडियोज़ पेश कर रहा है और इसका निर्माण ज़ी स्टूडियोज और बीलाइव प्रोडक्शन्स ने किया है। फिल्म 'राहु केतु' 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अन्विता को निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा : सुम्बुल तौकीर खान

मुंबई। अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर खान का कहना है कि सोनी सब के शो 'इत्ती सी खुशी' में अन्विता का किरदार निभाना उनके लिये बेहद चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है। सोनी सब का शो 'इत्ती सी खुशी' अन्विता (सुम्बुल तौकीर खान) की दिल छू लेने वाली यात्रा दिखाती है, जिन्होंने हमेशा अपने पिता सुहास (वरुण बडोला) और भाई-बहनों के लिए मजबूती से खड़े रहना सीखा है। उसकी जिंदगी तब जटिल मोड़ लेती है जब विराट (रजत वर्मा) वही शख्स जिसने सगाई के दिन उसे छोड़ दिया था, लौटकर एक और मौका मांगता है, जबकि अन्विता स्पष्ट रूप से कहती है कि वह उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। जैसे ही वह संजय (ऋषि सक्सेना) के साथ आगे बढ़ती है, जिसके छिपे हुए मकसद नए संकट खड़े करते हैं, अन्विता को पुराने घावों और एक अनिश्चित भविष्य के बीच रास्ता निकालना पड़ता है। आने वाले एपिसोड में, अन्विता की शादी की पहली रात तब बिखर जाती है, जब उसे अपनी मां हेतल (नेहा एसके मेहता) के बारे में छिपे हुए कई सच का पता चलता है। वह महिला जिसने एक समय अपने बच्चों को छोड़ दिया था, प्यार से लौटकर नहीं आई थी, बल्कि उसके पीछे एक और मकसद था। अन्विता को पता चलता है कि हेतल चुपके से अपने ससुराल में संजय की सुरक्षा में रह रही थी जिससे बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। हेतल का अस्थिर व्यवहार भावनात्मक गर्मजोशी से लेकर परेशानी तक अचानक बदलता है, और एक मोड़ पर वह अचानक बेहोश हो जाती है। क्लिनिक में अन्विता को बताया जाता है कि हेतल की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उस पर सावधानी से नजर रखने की जरूरत है।

बॉक्स ऑफिस पर गूंजा 'धुरंधर' का दबदबा

अभिनेता रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित जासूसी एक्शन-थ्रिलर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाका कर चुकी है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज पांच दिनों में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। दर्शक फिल्म के शानदार निर्देशन, दमदार स्क्रीनप्ले और रणवीर के पावरफुल परफॉर्मेंस की खूब सराहना कर रहे हैं। वीकडेज़ में भी 'धुरंधर' का जबरदस्त क्रेज़ बना हुआ है, जिससे इसकी कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृति सैनन की 'तेरे इश्क में' कारोबारी दिनों में थोड़ी सुस्त नजर आने लगी है। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 26.50 करोड़ रुपये की बेहतरीन कमाई की। यह सोमवार के कलेक्शन (23.25 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है। अब तक भारत में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 152.75 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी 'धुरंधर' की कमाई का तूफान जारी है और पांच दिनों में फिल्म ने लगभग 225 करोड़ रुपये का ग्लोबल कलेक्शन कर लिया है। इसका निर्देशन और लेखन आदित्य धर ने किया है। उधर, धनुष और कृति सैनन स्टारर 'तेरे इश्क में' ने 12 दिन पूरे कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 11वें दिन 2.4 करोड़ रुपये और 12वें दिन 2.85 करोड़ रुपये की कमाई की। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने भारत में कुल 105.25 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 145.38 करोड़ रुपये का संग्रह कर लिया है। दोनों फिल्मों की तुलना में जहां 'धुरंधर' तेजी से आगे निकलती दिख रही है, वहीं 'तेरे इश्क में' स्थिर लेकिन धीमी रफ्तार से कमाई जारी रखे हुए है।

विदेश

संक्षिप्त खबरें

श्रीलंका में दित्वा तूफान से हुए नुकसान से उबरने में छह महीने लगेंगे : मंत्री

कोलंबो। श्रीलंका के उप वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि चक्रवात दित्वा के कारण देश को हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक आकलन को पूरा करने में छह महीने लग सकते हैं। हालांकि, दित्वा के कारण हुए नुकसान का मोटे तौर पर अनुमान 15 दिसंबर के बाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस काम का जिम्मा 'रीबिल्ड श्रीलंका फंड' के हाथों में है, जिसका गठन राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने किया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बनी निधि प्रबंधन समिति को आवश्यकताओं का आकलन करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, संसाधनों का आवंटन करने और पुनर्निर्माण कार्य के लिए धनराशि वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। मावबिमा अखबार ने उप वित्त मंत्री अनिल जयंथा फर्नांडो के हवाले से बताया कि श्रीलंका के प्रवासी नागरिक एवं भारत सहित कई देश इस कोष में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुरोध किया है। सरकार का प्रारंभिक अनुमान है कि चक्रवात से हुए नुकसान से उबरने के लिए दो से तीन अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

नेपाल : नए कस्टम कानून के विरोध में देशभर में कस्टम का कामकाज बंद

काठमांडू। नए कस्टम कानून के विभिन्न प्रावधानों पर असहमति जताते हुए देशभर में कस्टम एजेंटों के पेनडाउन के कारण सभी कस्टम कार्यालय का कामकाज पूरी तरह बंद हो गया है। इसका सीधा असर आयात-निर्यात पर हो रहा है। गत शनिवार से लागू हुए नए कस्टम कानून में दंड-जुर्माना कठोर होना, कागजात एवं जाँच–पास प्रक्रिया अव्यावहारिक होना जैसे कारणों का हवाला देते हुए एजेंटों ने मंगलवार सुबह से पूरे देश के कस्टम कार्यालयों में काम रोक दिया है। भंसार एजेन्ट महासंघ के आह्वान पर जाँच–पास प्रक्रिया ठप होने से आयात–निर्यात गतिविधियाँ बाधित हो गई हैं। मंगलवार की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने के कारण आज बुधवार को भी आयात–निर्यात ठप है। कस्टम विभाग का कहना है कि विवादित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा आवश्यक है। दंड और कागजात सम्बन्धी प्रावधान कानूनी ढांचे पर आधारित होने के कारण इन्हें तुरंत संशोधित करना संभव नहीं है; इसके लिए आर्थिक कानून में संशोधन करना होगा। कस्टम विभाग के महानिर्देशक श्याम भण्डारी ने कहा, "व्यावहारिक प्रकृति के विषयों का तुरंत समाधान किया जाएगा। कस्टम प्रक्रिया में सहजता लाने वाले सुधारों को विभाग प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ेगा।

पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ रहे थे, मैंने युद्ध खत्म करवाया: ट्रंप

न्यूयॉर्क/पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे को फिर से दोहराते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान में "जंग छिड़ी हुई थी" और उन्होंने ही परमाणु हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष को समाप्त कराया। ट्रंप अब तक लगभग 70 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को रुकवाया था। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के माउंट पोकोनो में अर्थव्यवस्था पर एक रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "दस महीनों में मैंने आठ युद्ध समाप्त करवाए जिनमें कोसोवो (और) सर्बिया, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया... आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं, वे आपस में लड़ रहे थे।

भारत ने छह और सात मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसके तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष समाप्त करने के लिए 10 मई को सहमति बनी। भारत ने संघर्ष के समाधान में किसी भी

तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। इसी बीच, ट्रंप ने कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और "कल" वह उन देशों को फोन करेंगे। ट्रंप ने कहा, "ऐसा कौन कह सकता है कि मैं एक फोन कॉल करके थाईलैंड और कंबोडिया जैसे दो बेहद शक्तिशाली देशों के बीच जारी युद्ध को रोक दूंगा? वे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यह करूंगा। इसलिए हम ताकत के बल पर शांति स्थापित कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं।" आव्रजन के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि 50 वर्षों में पहली बार अमेरिकी नागरिकों के लिए अधिक नौकरियां, बेहतर वेतन और उच्च आय सुनिश्चित हो पा रही है, न कि अवैध प्रवासियों के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान, हैती, सोमालिया और कई अन्य देशों जैसे "नरक जैसे स्थानों" से आने वाले प्रवासन पर स्थायी रोक लगाने की घोषणा की है।

पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि वह "तीसरी दुनिया (विकासशील/अविकसित देश) के सभी देशों" से प्रवासन को 'स्थायी रूप से रोक देंगे' और उन विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर देंगे जो 'सुरक्षा के लिए जोखिम' हैं क्योंकि उनके प्रशासन ने अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल द्वारा नेशनल गार्ड के एक सदस्य की हत्या के बाद आव्रजन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 19 उच्च जोखिम वाले देशों के नागरिकों की जांच करते समय "नकारात्मक, देश-विशिष्ट कारकों" पर विचार करने की अनुमति दी गई है। इन देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं।

उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्ण अधिवेशन की तैयारियां शुरू

सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और शीर्ष अधिकारियों ने पांच साल बाद होने जा रहे सत्तारूढ़ पार्टी के पहले पूर्ण अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक की। सरकारी मीडिया में बुधवार को यह खबर दी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से वार्ताएं दोबारा शुरू करना चाहते हैं, ऐसे में इस उच्चस्तरीय अधिवेशन में नयी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने खबर दी कि किम ने मंगलवार को वर्कर्स पार्टी की एक पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। खबर में कहा गया है कि इस दौरान पार्टी के अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ इस साल की सरकारी नीतियों की समीक्षा की गई। केसीएनए ने इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी। जानकारों के अनुसार पूर्ण बैठक कुछ दिन चलेगी, जिसमें पार्टी के अधिवेशन का आधिकारिक एजेंडा तय किया जाएगा। पार्टी का पूर्ण अधिवेशन जनवरी या फरवरी में आयोजित होने का अनुमान है। वर्कर्स पार्टी के पूर्ण अधिवेशन में पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। 36 साल के अंतराल के बाद 2016 में किम ने इसे फिर से शुरू किया। जानकारों का कहना है कि किम का उद्देश्य पार्टी के अधिकार को बढ़ाना था, ताकि सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके। इस अधिवेशन को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किम संबंध सुधारने के अमेरिका और उत्तर कोरिया के प्रयासों पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। उत्तर कोरिया ने वार्ताएं फिर से शुरू करने की अमेरिका और दक्षिण कोरिया की अपील को नकार दिया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अमेरिका से बातचीत अगले साल शुरू हो सकती है। ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए किम ने सितंबर में संकेत दिया था कि यदि अमेरिका उत्तर कोरिया के "परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी भ्रम की स्थिति" को छोड़ देता है, तो वार्ताएं फिर से शुरू हो सकती हैं।

नेपाल: बयान के लिए उपस्थित नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की गिरफ्तारी की तैयारी

काठमांडू। जेन जी आंदोलन के दौरान हुए अत्यधिक पुलिस बल प्रयोग की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक के बयान के लिए उपस्थित न होने की स्थिति देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर पेश कराने की तैयारी में है। इस आयोग की अवधि केवल दो सप्ताह शेष रहते हुए आयोग की तरफ से अब तक बयान का काम पूरा नहीं हो पाया है। फील्ड में तैनात सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान लेने के बाद अब आयोग राजनीतिक स्तर के बयान लेने की प्रक्रिया में है। आयोग के प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा के अनुसार लगभग डेढ़ सौ लोगों से बयान लेने का काम पूरा हो चुका है। अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल और नेपाल पुलिस प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की का बयान लेना बाकी है। आयोग की

सिफारिश के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की विदेश यात्रा और बिना अनुमति काठमांडू से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओली की तरफ से आयोग को असंवैधानिक बताते हुए बयान न देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। प्रवक्ता शर्मा का कहना है कि बयान लेने में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं आए, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग सरकार को कानूनी रूप से उन्हें पेश कराने का अनुरोध करेगा। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग लिखित अनुरोध करता है तो सरकार पुलिस भेज कर उन्हें उपस्थित कराएगी। गृहमंत्री ने कहा रकानून सबके लिए समान है। उम्मीद है कि वे मानेंगे; न मानने पर कानून लागू किया जाएगा। जांच आयोग के प्रवक्ता शर्मा के अनुसार बयान लेना अनिवार्य होने के कारण ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रक्रियागत रूप से जल्द से जल्द बयान लेने का निर्णय आयोग कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख सचिव, संसद महासचिव और सुरक्षा निकायों के प्रमुख तक आयोग में आकर बयान दे चुके हैं। इधर, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ने कहा कि "आयोग स्वयं अमान्य है इसलिए पूर्व प्रधानमन्त्री ओली के बयान के लिए उसके समक्ष जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम पहले ही इसकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठा चुके हैं और इसे अस्वीकार्य घोषित किया है। आयोग ने मंगलवार को सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल का बयान लिया। उन्हें आवश्यकता होने पर फिर बुलाया जाएगा। इससे पहले पूर्व पुलिस प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुंग को भी पुनः बुलाए जाने की संभावना आयोग ने जताई थी।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी ने जेल में अपने अनुभव साझा किए

पेरिस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने अपनी एक किताब में उस जेल का वर्णन किया है, जहां उन्होंने 20 दिन बिताए थे। सरकोजी ने जेल को शोरगुल वाली जगह, कठोर और अमानवीय हिंसा से भरी दुनिया बताया है।

सरकोजी की इस पुस्तक का बुधवार को विमोचन किया गया जिसमें इस बारे में राजनीतिक सलाह भी दी गई है कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को धुर दक्षिणपंथी मतदाताओं को कैसे आकर्षित करना चाहिए। 'डायरी ऑफ ए प्रिजनर' नामक इस पुस्तक में 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अपराध के प्रति उनके अपने सख्त रुख ने एक नया रूप ले लिया है। सरकोजी को 2007 के अपने विजयी चुनावी अभियान को लीबिया से प्राप्त धन से वित्तपोषित करने के मामले में आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। अदालत ने सितंबर में सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की। करीब 20 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें न्यायिक निगरानी में रिहा कर दिया गया। यह पुस्तक पेरिस की ला सैंटे जेल के अंदर की दुर्लभ झलक पेश करती है, जहां सरकोजी को एकांत कारावास में रखा गया था और सुरक्षा कारणों से उन्हें अन्य कैदियों से सख्ती से अलग रखा गया था।

उनकी एकांतता केवल उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी-सरकोजी और उनके वकीलों की नियमित मुलाकातों से ही टूटती थी। सरकोजी ने लिखा कि उनकी कोठरी "एक सस्ते होटल जैसी दिखती थी, सिवाय बख्तरबंद दरवाजे और सलाखों के", जिसमें एक सख्त गद्दा, प्लास्टिक जैसा तकिया और एक ऐसा शॉवर था जिससे केवल पानी की पतली धार निकलती थी।

उन्होंने जेल के शोर का वर्णन किया, जिसमें से अधिकांश शोर रात के समय होता था। सरकोजी ने जेल के माहौल को भयावह बताते हुए उसे नरक करार दिया। सरकोजी का कहना है कि उन्हें जेल में रहने के दौरान घटी कई हिंसक घटनाओं की जानकारी मिली। जेल में बिताए गए समय का वर्णन करने के अलावा, सरकोजी ने इस पुस्तक का उपयोग अपनी कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी के लिए रणनीतिक राजनीतिक सलाह देने के लिए किया। सरकोजी ने पुस्तक में खुलासा किया कि उन्होंने जेल से फोन पर धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन से बात की थी, जो कभी उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी थीं।